राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHI/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 294 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,28 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

प्रधानमंत्री की चाची का कोरोना से निधन

अहमदाबाद, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाची नर्मदाबेन मोदी का मंगलवार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस से निधन हो गया। वह पिछले 10 दिनों से संक्रमित थीं। प्रधानमंत्री के छोटे भाई प्रह्लाद मोदी ने कहा, कोरोना वायरस संक्रमण से तबीयत बिगड़ने पर हमारी चाची नर्मदाबेन को करीब दस दिन पहले सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रह्लाद मोदी ने कहा, उन्होंने आज अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने कहा कि उनकी चाची के पति जगजीवनदास, प्रधानमंत्री के पिता दामोदरदास के भाई थे और उनकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी।

पीआईबी अधिकारी संजय कुमार का निधन

नई दिल्ली। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार का आज सुबह कोविड-19 संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उन्हें बीते कल दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया था। पीआईबी में उप-निदेशक (मीडिया और संचार) संजय कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रचार आवश्यकताओं की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा वे पर्यटन मंत्रालय के प्रचार कार्य के साथ भी जुड़े हुए थे। आईआईएस में 34 वर्षों के शानदार करियर के दौरान उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत पीआईबी की विभिन्न प्रचार इकाइयों को अपनी सेवाएं दीं।

कोरोना की रफ्तार हुई कुछ कम

लखनऊ, (एजेंसी)। यूपी में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का प्रकोप मंगलवार को कुछ कम दिखा। पिछले एक सप्ताह से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे थे। बीते दिनों कोरोना के आंकड़े 38 हजार तक पहुंच गए थे। मंगलवार को यूपी में कोरोना के 32 हजार 993 नए मामले सामने आए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 30 हजार 398 संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर मांगी जानकारी

नई दिल्ली । देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी, हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते हैं। हम हाईकोर्ट्स की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते पैदा हुए राष्ट्रीय संकट के इस समय अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती है। इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना बिल्कुल नहीं है, हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने कहा- वैक्सीनेशन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है- सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एसआर भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारनटीन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस पर क्या राष्ट्रीय योजना है? कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो फिर क्या है? दरअसल, अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग-अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता के स्टरलाइट प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन उत्पादन करने का आदेश जारी किया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी तय करेगी कि प्लांट के भीतर कितने लोगों की जरूरत है। वेदांता इस प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन करेगा। इसके जरिए फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा। दरअसल, तीन साल से बंद पड़े तमिलनाडु में वेदांता स्टरलाइट प्लांट को खोलने के लिए याचिका लगाई गई थी। वेदांता की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वेदांता स्टारलाइट प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट चालू करना चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय आपदा है- इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय आपदा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक कलह नहीं होनी चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाजत दी है। गौरतलब है कि इस सुनवाई से पहले तमिलनाडु सरकार ने वेदांता के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट को आंशिक तौर पर खोलने की अनुमति दे दी।

बता दें कि कोरोना को लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस इस रविन्द्र भट की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील साल्वे से पूछा कि आप संयंत्र को कब से शुरू कर सकते हैं। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।

कोरोना संकट :भारत को 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रहा आयरलैंड

नई दिल्ली । आयरलैंड ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये मदद के तौर भारत को 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य चिकित्सा सामग्री भेजने की मंगलवार को घोषणा की. आयरलैंड दूतावास ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बुधवार सुबह तक भारत पहुंचने की उम्मीद है. दूतावास ने कहा, 'आयरलैंड रोगियों के इलाज में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए भारत को 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रहा है. कंसंट्रेटर्स के बुधवार तड़के भारत पहुंचने की उम्मीद हैं.'

आयरलैंड के राजदूत ब्रेंडन वार्ड ने कहा कि आयरलैंड भारत सरकार से करीबी संपर्क बनाए हुए है और महामारी से निपटने में भारत की और अधिक सहायता के रास्ते तलाश रहा है.

इससे पहले यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट आज यानी मंगलवार सुबह भारत पहुंचा है. इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आए हैं. एयर इंडिया अमेरिका और भारत के बीच अपनी दो उड़ानों से करीब 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर आएगी. एयर इंडिया का एक विमान न्यूयार्क एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है.

ब्रिटेन ने भी भेजी पहली खेप

भारत की मदद करने वालों में थाइलैंड भी शामिल है जहां से ऑक्सीजन कंटेनर्स का एक और कंसाइमेंट भारत पहुंच गया है. भारत में कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से निपटने में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने में मदद के लिए ब्रिटेन से जीवन रक्षक सहायता पैकेज की पहली खेप भेजी है.

विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) द्वारा भुगतान की गई आगामी खेप का प्रबंध इस सप्ताह के दौरान किया जा रहा है और इसमें 9 एयरलाइन कंटेनर लोड शामिल होंगे. इसमें 495 ऑक्सीजन संकेन्द्रक, 120 नॉन-इंवेजिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर शामिल हैं.

चुनाव नतीजों के दिन नहीं मनेगा जीत का जश्न, इलेक्शन कमीशन ने लगाया बैन

नई दिल्ली । 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं. ऐसे में अब कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और चुनाव नतीजों के दिन किसी भी तरह के सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है. इसी के साथ ये भी कहा गया है कि विजेता उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे.

चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सोमवार को ही मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी और कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया था. कहा कि कोरोना संक्रमण के रोजाना बढ़ते मामलों के बावजूद चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को रैलियां करने की इजाजत कैसे दे दी? देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के बाद भी आयोग ने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया.

मद्रास हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों के दौरान कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में असफल रहने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई. मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने कहा, 'कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है'. माना जा रहा है कि ये कोर्ट की फटकार का ही असर है कि चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है.

न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी ने कहा था, 'चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि रैलियों के दौरान कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया था. इसपर कोर्ट ने कहा, 'क्या आप तब दूसरे ग्रह पर थे जब राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया जा रहा था'.

मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा कि नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ही ये बात बतानी पड़ रही है. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि 2 मई को होने वाली मतगणना के दिन अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ तो मतगणना पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी.

कोर्ट ने कहा कि बात अब सुरक्षा की है, बाकी सब कुछ इसके बाद आता है. हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य सचिव के साथ सलाह मशविरा करके 30 अप्रैल तक कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार करें और यह सुनिश्चित करें कि मतगणना के दिन कोरोना नियमों का सही तरीके से पालन हो.

बिहार के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ेगी

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोविड-19 से संबंधित स्थितियों की समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिये। कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी और बढ़ने की आशंका है। इसके मद्देनजर आलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआईएमएस सहित सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ायी जाए।

एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से सोमवार की दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्य में और तेजी लाएं। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ जांच की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, इससे संक्रमितों का समय पर इलाज किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क का वितरण सुनिश्चित कराएं और लोगों को मास्क के प्रयोग के बारे में जानकारी दें। बैठक के आरंभ में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में कोविड-19 की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सकों, यूनानी चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, सेवानिवृत चिकित्सकों का भी इस महामारी से निबटने में सहयोग लें।अन्य प्रकार के चिकित्सा कार्य से भी जुड़े लोगों की ट्रेनिंग कराकर उनका सहयोग लिया जाय।

बैंकाक से किया जाएगा 18 टैंकर ऑक्सीजन का आयात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया। हमने केंद्र से इसके लिए वायुसेना के विमानों के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में बातचीत जारी है, मुझे उम्मीद है बातचीत सफल होगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बैंकॉक से आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और राष्ट्रीय राजधानी में आईसीयू बेड बढ़ाने की बात की। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर ऑक्सीजन आयात करने का निर्णय लिया है, वे कल से शुरू करेंगे। हमने केंद्र से इसके लिए वायुसेना के विमानों के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसके परिवहन को लेकर बातचीत की जा रही है।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

महाकुंभ 2021 चैत्र पूर्णिमा शाही स्नान के बाद सकुशल सम्पन्न

हरिद्वार। महाकुंभ 2021 के आखिरी चैत्र पूर्णिमा शाही स्नान पर तड़के से ही श्रद्धालुओं का हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने का क्रम लगातार लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान करते हुए पुण्य अर्जित करते हुए मां गंगा सहित मन्दिरों में पूजा अर्चना करते हुए परिजनों व शुभचिंतकों की कुशलता की कामना की। जिसके पश्चात अखाडों के निर्धारित समय से पूर्व ही हरकी पौडी ब्रह्मकुण्ड को खाली करवाते हुए घाटों की साफ सफाई कराते हुए संतों के स्नान के लिए घाटों को सुरक्षित कर दिया गया। श्री पंचायत निरंजनी अखाडे ने सचिव रविन्द्र पुरी के नेतृत्व में सीमित संत महात्मा प्रतीकात्मक रूप से स्नान के लिए पहुंचे। जहां पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने संतों का स्वागत किया। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े ने अपने आराध्य देव और मां गंगा की पूजा अर्चना के पश्चात कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए संतजन मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर शाही स्नान कर वापस छावनी लौटे। इसके पश्चात श्री दशनाम जूना अखाड़ा, श्री अग्नि और आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने राष्ट्रीय महामंत्री व जूना अखाड़े के अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरिगिरि के नेतृत्व में हर हर महादेव का जयघोष करते हुए शाही स्नान किया। साथ ही किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अपने अखाड़े के संतों के साथ ब्रह्मकुण्ड में गंगा स्नान किया। इसके बाद निर्धारित क्रमों व समयानुसार श्री महानिवार्णी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संतों ने हरकी पौडी ब्रह्मकुण्ड पहुंचकर चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान किया। इसके बाद अखिल भारतीय श्री पंच निमोर्ही अणि अखाड़े के संतजन शाही स्नान के लिए ब्रह्मकुंड पहुंचकर जय श्री राम और हर-हर महादेव का जयघोष कर शाही स्नान किया। वहीं अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अणि और श्री निवार्णी अणि अखाडे के संतों श्रीमहंत धर्मदास, श्रीमहंत गौरीशंकर दास, श्रीमहंत राजेन्द्र दास, रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज सहित अन्य संतों ने हरकी पौडी पहुंचकर ब्रह्मकण्ड में शाही स्नान किया। श्री निवार्णी अणि अखाड़े के महंत गौरीशंकर दास ने साधु सन्यासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस और दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की। मेला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस के जवानों के कार्य की सराहना कर सभी के लिए मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का नाश अवश्य होगा, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आईजी कुंभ संजय गुंज्याल ने स्नान के पहले और स्नान के बाद मास्क की अपील करते हुए संतजनों के सहयोग के लिए आभार जताया।

आयुष मंत्रालय ने यूनानी व आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए आयुष मंत्रालय समय-समय पर कुछ दिशानिर्देश जारी करता रहता है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, खानपान, दिनचर्या, इलाज, बचाव आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से आयूष मंत्रालय ने सोमवार (27 अप्रैल) को होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए आयुर्वेद व यूनानी डॉक्टरों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया, मौसमी बदलावों को देखते हुए रोगी के संविधान में सलाह दी गई है कि वासा (मालाबार नट), यष्टिमधु (लिकोरिस रूट) और गुडूची (गिलोय) को आवश्यकता के अनुसार क्वाथ में जोड़ा जा सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान देते हुए होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों के दिशानिदेर्शों के बारे में तत्काल जानकारी प्रसारित करने की आवश्यकता है। गाइडलाइन में कहा गया,घरेलू साक्ष्य के दौरान कोरोना केहल्के मामलों के प्रबंधन के लिए आयुष- 64, अश्वगंधा की गोलियांआदि जैसे प्रभावी साक्ष्य- आधारित आयुर्वेद और यूनानी योगों / उपायों को शामिल किया गया है।

हाई कोर्ट ने 5 रिफिलर्स के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस, कार्रवाई का आदेश

नई दिल्ली । दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कालाबाजारी करने वाले रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम सेठ के रुख को पूरी तरह से गलत और अविश्वसनीय मानते हैं। अग्रवाल इस दावे से इनकार करते हैं। यह स्पष्ट है कि सेठ आक्सीजन आपूर्ति को विचलित कर रहा है और शायद काले बाजार में बेच रहा है।हाई कोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंधन नहीं कर पा रही है तो आप हमें बताइए हम केंद्र सरकार को कहेंगे कि वे इसे ओवर टेक करें।

वहीं, हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरों पर सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिलेंडर (ऑक्सीजन) का कारोबार पूरी तरह गड़बड़ है। कालाबाजारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें, फिर कोटा तीन दिनों के लिए आवंटित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कोटा अभी जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी किया जाएगा। इसे इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा। यदि अस्पतालों को कोई शिकायत है तो एक प्रावधान रखा जाएगा, एक समर्पित संख्या होगी और हम बदलाव करने के लिए तैयार होंगे।

वेंकटेश्वर अस्पताल के वकील ने कहा कि यह एक आपातकालीन स्थिति है, ऑक्सीजन अस्पताल से खत्म होने वाली है।नोडल अधिकारी सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत सभी के पास आ रही है, तो इसमें कुछ सच्चाई होगी। अदालत ने कहा कि बार-बार कॉल और मैसेज का जवाब नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं।

कोर्ट ने कहा मुख्य सचिव से कहा कि आप जिस आदेश की बात कर रहे हैं, वह अस्पतालों के लिए है। व्यक्तियों के बारे में क्या, जो अपने सिलेंडर घर पर रिफिल करवाना चाहते हैं?। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कुछ सौ रुपये में मिलते हैं वह लाखों में बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करें। हाई कोर्ट के समक्ष एक अन्य अस्पताल ने कहा कि रेमेडीसविर और ऑक्सीजन की कमी है। शांति मुकुंद अस्पताल के वकील ने कहा कि उनके यहां ऑक्सीजन का स्टाक शाम छह बजे तक ही है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में एलएनजेपी के सामने रामलीला मैदान में 500 अन्य आईसीयू बेड बनाने के लिए एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया।

रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर ब्राजील ने जताया संदेह, इस्तेमाल से किया इनकार

ब्राजीलया। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने सोमवार को साफ तौर पर रूस से वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंगवाने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन Sputnik V के सुरक्षित और कारगर साबित करने वाले आंकड़े उनके पास नहीं है। स्वास्थ्य नियामक से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, हम ब्राजील के लाखों लोगों ऐसे उत्पाद का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं देंगे जिसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर संदेह हो।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक एलेक्सेई नवलनी के समर्थकों को गतिविधियां बंद करने के आदेश

मॉस्को। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक एलेक्सेई नवलनी के समर्थकों के प्रदर्शन और गतिविधियां रोकने की तैयारी हो गई है। सोमवार को सरकार ने नवलनी की पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालयों को अपनी गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए। रूसी सरकार के अनुसार यह आदेश एक अदालत के निर्देश के अनुरूप हैं। अदालत में बंद दरवाजों के पीछे हुई सुनवाई में नवलनी के एंटी करप्शन फाउंडेशन और उनके समर्थकों की गतिविधियों को कानून के खिलाफ माना गया। मॉस्को के सरकारी वकीलों ने अदालत में नवलनी के संगठन और उनके नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाने की अर्जी दी थी। कहा, नवलनी रूस को तोड़ना चाहते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार उसी पर सुनवाई कर अदालत ने नवलनी के समर्थकों की गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया। नवलनी के चलते रूस इन दिनों चर्चा में है। वहां पर कोरोना संक्रमण फैले होने के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लोगों की भीड़ जुट रही है। ये लोग नवलनी की जेल से रिहाई की मांग कर रहे हैं।

नवलनी ने हाल ही में अपना तीन हफ्ते चला अनशन खत्म किया है। उनके इस अनशन पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। रूस के कानून के अनुसार नवलनी को अदालत ने यदि अतिवादी घोषित कर दिया तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई के व्यापक अधिकार मिल जाएंगे। तब सरकार नवलनी और उनके संगठन के बैंक अकाउंट से लेन-देन रोक सकेगी। कार्यालयों को बंद करा सकेगी। समर्थन में हो रहे आंदोलन को रोक सकेगी और उसमें शामिल लोगों को लंबे समय के लिए गिरफ्तार कर सकेगी।

पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं अलकायदा जैसे संगठन, अमेरिकी जनरल ने किया आगाह

इस्लामाबाद। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद आतंकवादी दोबारा संगठित होने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं। अन्य पड़ोसी देश भी इन संगठनों से प्रभावित रहेंगे। यह जानकारी पेंटागन की पत्रकार वार्ता के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जूनियर कमांडर जनरल कैनेथ एफ मैकेंजी ने दी। उन्होंने कहा कि अगर निरंतर दबाव नहीं बनाया गया तो ये संगठन दोबारा एकजुट होने में सक्षम हैं। ऐसी स्थितियां अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों विशेषकर पाक के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। जनरल मैकेंजी पर पाक और अफगान में अमेरिकी सेना की गतिविधियों की जिम्मेदारी है।

मैकेंजी ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना और राजनयिक इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि समस्या का हल करने के लिए आसपास के देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने पर समझौता किया जाए। जहां लड़ाकू विमानों को भी रखा जा सके, जो जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई कर सकें। हालांकि ऐसे निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर ही लिए जाएंगे। अफगानिस्तान में 18 साल पहले अमेरिका ने बलूचिस्तान के शम्सी हवाई अड्डे से इसी तरह से अफगानिस्तान में ड्रोन से हमले करते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक भारत के साथ सभी विवादों पर वार्ता के जरिये हल करना चाहता है। भारत को पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के संबंध में लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए। भारत ने इस दिन अनुच्छेद 370 हटाने सहित कई निर्णय लिए थे। तुर्की की मीडिया से बात करते हुए पाक के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत से वार्ता में हमें कोई परेशानी नहीं है। वार्ता के लिए उसे कश्मीर पर पहले विचार करना चाहिए। शाह महमूद ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर वार्ता कर सुलझाया जा सकता है।

कोरोना : पिछले 24 घंटे में 6.72 लाख केस

इनमें 47फीसदी मामले सिर्फ भारत में; तुर्की में 17 मई तक लॉकडाउन

वाशिंगटन। दुनियाभर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 6 लाख 72 हजार 914 संक्रमितों की पहचान हुई और 10,767 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के आंकड़े की बात करें, तो सोमवार को दुनियाभर में आए केस के 47फीसदी मामले सिर्फ भारत में मिले। यहां 3 लाख 19 हजार 435 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई।

उधर, तुर्की में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यह 29 अप्रैल की शाम से लागू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस दौरान इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट पर भी लगाम लगाई है। ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही ऑपरेट कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

पाकिस्तान में सेना तैनात

पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को लागू कराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इमरान सरकार ने देश के 16 शहरों में सेना की तैनाती की है।

पाकिस्तान में लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, गैर-जरूरी बिजनेस को शाम के 6 बजे के बाद ऑपरेट करने पर रोक लगाई गई है।अमेरिका आने वाले समय में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 6 करोड़ डोज निर्यात करने की तैयारी में है। व्हाइट हाउस ने बताया कि देशभर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है।

अमेरिका में तीन वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। थाइलैंड के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरना पड़ा है। प्रयुत चान-ओचा पर 190 डॉलर यानी करीब 14 हजार 200 रुपए जुर्माना लगाया गया।

पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। यहां अब रोज 5 हजार के करीब नए मरीज मिल रहे हैं। देशभर में अभी 8 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान में 250 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भारत के हालात दिल दहलाने वाले : डब्ल्यूएचओ

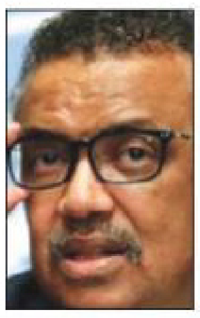

भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालातों पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई है। संगठन के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस ने कहा कि भारत में इस समय हालात दिल दहलाने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में वहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के परिजन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि भारत कोविड-19 की भयानक लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। श्मशान घाट पर लाशों की कतार लगी है। ये स्थिति हृदयविदारक है।

अब तक 14.84 करोड़ संक्रमित

दुनिया में अब तक करीब 14.84 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 31.33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल 1.92 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1.91 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 1.11 लाख लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पाकिस्तान में शराब की कालाबाजारी

महामारी के दौरान तीन गुना तक बढ़े शराब के दाम, बड़े ब्रांड की शराब में पानी मिलाकर बेच रहे लोग

इस्लामाबाद। हामारी के दौर में पाकिस्तान में शराब की कालाबाजारी तेजी से बढ़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि लोग दो से तीन गुना दाम चुकाने के तैयार है। कालाबाजारी करने वाले बड़े-बड़े ब्रंड की शराब में पानी तक मिलाकर बेच रहे हैं। डॉयचे वेले की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुस्लिमों के लिए शराब पीना आधिकारिक तौर पर बैन है। लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो इन प्रतिबंधों की अनदेखी कर शराब का इस्तेमाल करती है। दक्षिणी सिंध प्रांत में गैर-मुस्लिम ग्राहकों के लिए शराब की दुकानें वैध हैं। कराची में ऐसी ही एक दुकान पर काम करने वाले हिंदू युवा राहुल बताते हैं कि वे उन सभी को शराब देते हैं, जो उन्हें पैसे देते हैं। वे कहते हैं- हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कई लोग शराब पीते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीने वाले का धर्म क्या है। हालांकि, राहुल यह भी मानते हैं कि सतर्क रहना काफी जरूरी है। राहुल हर महीने 50 हजार रुपए तक कमाते हैं।

यह उनकी पिछली कमाई से काफी ज्यादा है। पहले वे कपड़ा फैक्ट्री में मजदूर थे। इस्लामाबाद के उमर ने बताया- पहले कभी-कभी ही शराब पीता था, पर अब रोज पीता हूं। शराब की वजह से मुझे चिंताओं से निपटने में मदद मिलती है।' 38 वर्षीय पत्रकार हीरा ने बताया कि उन्होंने व्हिस्की की बोतल तीन गुना महंगी खरीदी, पर उसमें पानी मिला हुआ था। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ।

पाकिस्तान में 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने शराबबंदी कानून बनाया था। हालांकि बार और क्लबों को कुछ छूट दी गई थी। बाद में 1979 में जनरल जिया-उल-हक ने शराब को गैर-इस्लामिक घोषित करते हुए इस कानून को और कठोर बना दिया।

ड्रैगन की दगाबाज

दुनिया भर के देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वहीं चीन ने मेडिकल सप्लाई ले जा रही कार्गो उड़ानें रोकीं

बीजिंग। अमेरिका सहित कई देशों ने कोरोना संकट के दौर में भारत के लिए मदद की पहल की। लेकिन चीन ने मदद की पेशकश करने के बाद मेडिकल सप्लाई में रुकावटें पैदा कर दी हैं। चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिनों के लिए रोक दिया है। इन विमानों के जरिए भारत को अतिआवश्यक ऑक्सीजन कसन्ट्रेटर और अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की जा रही थी।

इस हरकत के बाद चीन के निजी कारोबारियों से भारत को मेडिकल उपकरण मिलने में परेशानी खड़ी हो गई है। यह भी शिकायत आ रही है कि चीनी निर्माताओं ने ऑक्सीजन संबधी उपकरणों की कीमतों को 35-40% तक बढ़ा दिया है। चीन से भारत को सामान पहुंचाने में लगने वाली फीस में भी 29% की वृद्धि की गई है। इससे दोनों देशों के कारोबारियों द्वारा तेजी से ऑक्सीजन कसन्ट्रेटर खरीदने और भारत को भेजने में बाधा उत्पन्न होगी। कंपनी ने शियान-दिल्ली सहित 6 मार्गों पर कार्गो सेवा स्थगित की है। कंपनी ने इसके लिए कोरोना से आयात में कमी का कारण बताया है।

अमेरिकी मदद का फैसला अच्छा, और कदम भी उठाए जाएं : राजा कृष्णमूर्ति

वाशिंगटन। अमेरिका में भारत मूल के एक प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसद ने कोरोना से निपटने में भारत को मदद मुहैया कराने के अमेरिकी सरकार के फैसले का स्वागत किया है लेकिन यह भी कहा कि मदद सांकेतिक या जुबानी जमाखर्च जैसी नहीं होना चाहिए। बाइडन प्रशासन को फौरन ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि बाइडन प्रशासन ने प्रतिबद्धता जताई है कि वे कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को कच्चे माल की आपूर्ति करेगा। यह स्वागत योग्य फैसला है। लेकिन यह समय मदद का दिखावा करने का नहीं है। हमें ठोस कदम उठाने होंगे।

कोरोनारोधी टीके के लिए भारत को कच्चा माल मुहैया न कराने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों और समर्थकों समेत कई हलकों से बाइडन प्रशासन की कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचना के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जैक सुलिवन ने रविवार को अपने भारतीय समकक्ष अजित डोभाल से टेलीफोन पर बात की। डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय सहायता प्रगतिशील विदेश नीति की पहचान है। उन्होंने कहा कि तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। खन्ना ने कहा कि बाइडन प्रशासन एस्ट्राजेनेका टीके की अतिरिक्त खुराकें भारत को मुहैया करा सकता है।

उल्लेखनीय है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को एक ट्वीट में कहा था कि महामारी की शुरुआत में जिस तरह भारत ने हमें मदद भेजी, ठीक उसी तरह हम भी भारत की मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं।

भारत की मदद के लिए 24 घंटे काम करेगा अमेरिका

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत ने सोमवार को कहा कि उनका देश कोरोना की भयावह स्थिति का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए 24 घंटे काम करेगा। टीकों के लिए कच्चा माल, वेंटिलेटर, आक्सीजन उत्पादन आपूर्ति और टीकाकरण विस्तार के लिए वित्तीय सहायता सहित हर तरह की मदद उपलब्ध कराएगा। राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने एक वर्चुअल संवाद में कहा, मैं भारत की भयावह स्थिति के बारे में बताने के लिए एक मिनट लेना चाहती हूं। वहां कोरोना के मामलों में हाल में हुई वृद्धि काफी भयानक है। ऐसे मुश्किल वक्त में अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को एक ट्वीट में कहा था कि महामारी की शुरुआत में जिस तरह भारत ने हमें मदद भेजी, ठीक उसी तरह हम भी भारत की मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं।

ट्रम्प की विदाई के ठीक पहले हुआ खेल

पेंटागन ने संदिग्ध कंपनी को दिए 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस

दुनिया के कुल इंटरनेट एड्रेस का फीसदी, करीब 30 हजार करोड़ रुपए है कीमत

लंदन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने और उनके पद छोड़ने के दौरान कई नाटकीय और आश्चर्यजनक घटनाएं दुनिया ने देखी थीं। उस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जो इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी बन गया।

दरअसल, जिस दौरान जो बाइडेन की शपथ हो रही थी और ट्रंप राष्ट्रपति पद से विदा होने के अंतिम क्षणों में थे उसी वक्त अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने रहस्यमयी कंपनी को 17.5 करोड़ इंटरनेट एड्रेस ट्रांसफर कर दिए थे। यह दुनिया के कुल इंटरनेट एड्रेस का चार फीसदी है। इसकी कीमत करीब 30 हजार करोड़ रुपए है।

जिस कंपनी को यह डाटा दिया गया, दस्तावेजों में उसका नाम ग्लोबल रिसोर्स सिस्टम्स एलएलसी दर्ज है। फ्लोरिडा स्टेट के रिकॉर्ड के अनुसार, पहली बार कंपनी अक्टूबर 2020 में दर्ज की गई। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस छद्म कंपनी ने कैलिफोर्निया का जो पता दिया उस पर इसका कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। यही नहीं उस पते पर कोई बिजनेस लाइसेंस भी है। कंपनी ने मीडिया के किसी फोन या मेल का जवाब नहीं दिया और न ही उसका कोई वेबपेज अस्तित्व में है।

इस कंपनी से जुड़े जिस एकमात्र व्यक्ति रेमांड साउलिनो के बारे में फ्लोरिडा रजिस्ट्री से सुराग मिल सका है, उसका नाम नेवादा कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में 2018 में फोरेंसिक साइबर स्पेस-इंटरनेट सर्विलांस इक्यूपमेंट कंपनी के मैनेजिंग मेंबर के रूप में सूचीबद्ध है। हालांकि इससे संपर्क करने की भी कोशिश सफल नहीं हो सकीं। लगातार फोन करने के बावजूद दूसरी ओर से ऑटोमेटेड रिप्लाई ही मिला।

जिसे 30 हजार करोड़ का डेटा दिया उसके पते पर कोई नहीं

कैलिफोर्निया की कंपनी ग्लोबल रिसोर्स सिस्टम्स ने न फोन का जवाब दिया न मेल का, वेबपेज भी नहीं है

पेंटागन ने कहा- यह कमियों के आंकलन का पायलट प्रोजेक्ट, पर कंपनी यही क्यों चुनी नहीं बता सके

अब इस कंपनी के नियंत्रण में कॉमकास्ट और एटीएंडटी जैसे सबसे बड़े इंटरनेट प्रदाताओं से ज्यादा स्पेस है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, यह आईपी एड्रेस का अनधिकृत उपयोग रोकने उसका आकलन के लिए प्रचार का पायलट प्रोजेक्ट था। प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं दे सके कि जिस कंपनी का सितंबर, 2020 तक अस्तित्व नहीं था उसे इतने बड़े स्पेस को मैनेज करने के लिए क्यों चुना गया? नेटवर्क संचालक कंपनी केंटिक के निदेशक डग मैडोरी कहते हैं, यह इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी व रहस्यमय घटना है। पेंटागन ने जो स्पेस ट्रांसफर किया वह उसका दोगुना है जो वह खुद इस्तेमाल करता है। 20 जनवरी को बाइडेन की शपथ के दिन इंटरनेट के वैश्विक रूट पर एक कंपनी ने यह जानकारी दी।

कोरोना से निपटने के लिए यूएई से सबक:आबादी से 4 गुना टेस्ट किए

90फीसदी आबादी को वैक्सीन की एक डोज और 39फीसदी लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं

वाशिंगटन। हम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बैठकर कोरोना की बात करते हैं तो एक बात बाकी देशों से अलग रही है। सरकार ने पहले लोगों के मन से कोरोना के डर को हटाया। फिर संक्रमण पर काबू किया। आम जनजीवन वापस पटरी पर लौट चुका है। सब चीजें नार्मल तरीके से पुराने ढर्रे पर लौट चुकी हैं।

हालांकि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग और सारे एहतियात का पालन अब भी कर रहा है। यह लड़ाई मनोवैज्ञानिक और जमीनी स्तर पर लड़ी गई। बीते साल मार्च में सरकार ने व्यवस्थित ढंग से लॉकडाउन किया। पहले स्कूल और धार्मिक स्थल बंद किए। फिर चरणबद्ध तरीके से गैरजरूरी प्रतिष्ठानों को बंद किया। रात में पूरी तरह मूवमेंट रोक दिया।

यहां लोगों को लॉकडाउन में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वाजिब वजह से बाहर जाने के लिए ऑनलाइन पास आसानी से मिलता रहा। ग्रॉसरी स्टोर और गैर कोरोना मरीजों के लिए हॉस्पिटल कभी बंद नहीं हुए। दूसरी बात, यहां के नागरिकों का सरकार पर भरोसा और सरकार द्वारा लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, जिससे सबको सही हालात की सूचना मिलती रही और सबने अपने स्तर पर एहतियात बरती। चाहे हॉट स्पॉट्स की निगरानी का मसला हो या टेस्टिंग या हजारों बिस्तर के अस्पताल बनाने का मसला हो, यूएई की सरकार ने हर कदम पर मिसाल कायम की।

यह ऐसा देश है, जहां क्वारेंटाइन के दौरान लोगों को 5 सितारा होटल में भी रखा गया। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हफ्ते में 2 बार हॉलीवुड-बॉलीवुड की फिल्में दिखाईं। जब एक मरीज 5 स्टार होटल या अपने पसंद के खाने की व्यवस्था या फिर फिल्म देखते हुए वीडियो पोस्ट करता तो वह संदेश व्यवस्था से कहीं बड़ा होता है। इन सबसे लोगों के बीच डर खत्म हुआ। हालांकि सख्ती भी करनी पड़ी। रमजान में ही अबूधाबी पुलिस ने नियम

तोड़ने पर 39 सामाजिक समारोहों पर जुर्माना लगाया है। यहां रमज़ान में 10 से अधिक लोगों की सभा पर रोक है। आयोजकों के लिए जुर्माना 2 लाख और प्रतिभागी के लिए 1 लाख रुपए है। दुबई में मार्च में 11 दुकानों को सील किया गया। सरकार ने सूचना तंत्र पर निगाह बनाए रखी। पॉजिटिव पाए जाने के बाद, सरकार के आदेश के बावजूद हॉस्पिटल में न भर्ती होने या होम क्वारेंटाइन के दौरान नियम न मानने वालों पर 10 लाख रुपए के जुर्माने लगाए। शुरू में लोगों को गलती का अहसास कराने के लिए अखबारों में उनके फोटो छापे गए।

जनता ने भरोसा किया, पाबंदी मानी, टेस्ट के लिए लंबी कतारों में लगे

टेस्टिंग से तोड़ी संक्रमण की चेन, मामले कम हुए पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे उपाय अभी जारी: देश की पूरी 97.7 लाख आबादी का कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। लोगों के दिलों से कोरोना का डर निकल चुका था तो टेस्टिंग सेंटर्स और ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर्स पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखी गईं। किसी के मन में टेस्ट और वैक्सीन को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है।

एक महीने से रोजाना 1700 से 2000 के बीच आ रहे मामले, कुल 5 लाख केस आए, 1571 मौतें: संक्रमण की बात करें एक महीने से नए मामलों की संख्या 1700-2000 के बीच है। लेकिन 97.7 लाख आबादी वाले देश में 1.2 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसमें 90% को पहली और 39.4% आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं। देश की आबादी से चार गुना ज्यादा करीब 4.3 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं।

मरीजों का टेस्ट और पूरा इलाज फ्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लगातार लेते हैं हालचाल

18 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए बाबर सिद्दीकी बताते हैं कि जब रिपोर्ट आई तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी ने फोन करके पहले तो हालचाल पूछा। फिर एक सेंटर पर बुलाकर सारे टेस्ट, ऑक्सीजन, एक्सरे, सीटी स्कैन करने के बाद दवाएं दी गईं। एक वाच बैंड भी दिया गया, ताकि प्रशासन सेहत पर नजर रख सके। हेल्थ व कॉल सेंटर में सभी भाषाओं के जानकार डॉक्टर-काउंसलर हैं ताकि कोई असुविधा न हो। मार्च में विजिट वीसा पर आए बंगाल के सुवम पॉल कहते हैं कि यहां आने के बाद मैं पॉजिटिव हो गया।

संक्षिप्त खबर

दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार से पूछा अब तक क्या हुई कार्रवाई

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की खबरों पर सरकार से नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कालाबाजारी करने वालों को हिरासत में लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सिलेंडर (ऑक्सीजन) का कारोबार पूरी तरह गड़बड़ है। कालाबाजारी की सूचनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। हमने करने बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि वह अधिकारियों के साथ बात करेंगे और वेंकटेश्वर अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे दिल्ली में अपने केंद्र पर पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकरों का विवरण दें, फिर कोटा तीन दिनों के लिए आवंटित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कोटा अभी जारी नहीं हुआ है, आदेश जारी किया जाएगा। इसे इस अदालत के समक्ष रखा जाएगा। यदि अस्पतालों को कोई शिकायत है तो एक प्रावधान रखा जाएगा, एक समर्पित संख्या होगी और हम बदलाव करने के लिए तैयार होंगे। वेंकटेश्वर अस्पताल के वकील ने कहा कि यह आपातकालीन स्थिति है, ऑक्सीजन अस्पताल से खत्म होने वाली है।नोडल अधिकारी सुबह से जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत सभी के पास आ रही है, तो इसमें कुछ समस्या होगी। अदालत ने कहा कि बार-बार कॉल और मैसेज का जवाब नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा मुख्य सचिव से कहा कि आप जिस आदेश की बात कर रहे हैं, वह अस्पतालों के लिए है। व्यक्तियों के बारे में क्या, जो अपने सिलेंडर घर पर रिफिल करवाना चाहते हैं?। कोर्ट ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों में बेचे जा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करें।

अशोका होटल के 100 कमरों को बनाया कोविड केयर सेंटर

नई दिल्ली । देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारत में कोरोना संक्रमण की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में पड़ रही है. इस बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस और अन्य न्यायिक अधिकारियों व उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अहम फैसला लिया है. चाणक्यपुरी स्थित अशोका होटल को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए कोविड-19 फैसिलिटी केयर के रूप में तब्दील कर दिया है. इसमें कोरोना संक्रमित न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के लोग भी रह सकेंगे. यहां उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार ने प्राइमस हॉस्पिटल को अशोका होटल में कोविड हेल्थ सेंटर चलाए जाने की जिम्मेदारी दी है.

अस्पताल उठाएगा सारी जिम्मेदारी- चाणक्यपुरी एसडीएम के आदेश के तहत अगर कोविड केयर सेंटर के संचालन के दौरान होटल स्टाफ की संख्या में कमी होती है, तो इसकी व्यवस्था भी अस्पताल ही करेगा. सरकार ने इस सेंटर के साथ समन्वय के लिए एक अधिकारी की भी तैनाती की है. आदेश में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार मीणा इस सेंटर के संचालन के लिए प्राइमस हॉस्पिटल और होटल के साथ समन्वय बनाए रखेंगे. दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 20,201 नए मामले सामने आए जबकि एक ही दिन में सर्वाधिक 380 मरीजों ने इस घातक वायरस के कारण दम तोड़ दिया. नए मामलों के साथ ही शहर में अब तक 10.47 लाख से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं जबकि मृतक संख्या बढ़कर 14,628 तक पहुंच गई है. इसके मुताबिक, दिल्ली में संक्रमण की दर 35.02 फीसदी है. शहर में फिलहाल 92,358 मरीज उपचाराधीन हैं. बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 22,055 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं. इस दौरान 57,690 नमूनों की जांच की गई. वहीं इस दौरान 43,637 लोगों को टीके लगाये गए.

ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी के बीच दिल्ली से पंजाब पलायन कर रहे कोविड मरीज, अस्पतालों पर बढ़ा दबाव

नई दिल्ली । कोरोना का कहर से पूरे देश में तबाही का मंजर दिख रहा है. कहीं पर ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है तो कहीं पर समय रहते अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं. राजधानी दिल्ली में तो स्थिति इतनी विस्फोटक है कि अब रोज के 300 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं. ऑक्सीजन की भी ऐसी कमी है कि अब अस्पताल मरीजों को एडमिट भी नहीं कर पा रहे हैं. इस बीच बताया जा रहा है कि अब दिल्ली और दूसरे पड़ोसी राज्यों से कोविड मरीजों का पलायन शुरू हो गया है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली से कई कोविड मरीज अब इलाज के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं. दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ऐसे में कई मरीज पंजाब के अस्पतालों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली से आए कई मरीजों को पटियाला और जालंधर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है. वहीं हिमाचल और जम्मू से भी कई कोविड मरीज पंजाब के अस्पतालों में भर्ती हुए हैं. अस्पताल प्रशासन की मानें तो वे किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से लगातार आ रहे मरीज उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं.

पंजाब में इलाज करवा रहे दिल्ली के मरीज- पटियाला के सिविल सर्जन सतिंदर सिंह बताते हैं कि इस समय राजिंदर अस्पताल में दिल्ली से आए 14 कोविड मरीज भर्ती हैं. वहीं जालंधर के अस्पतालों में बाहरी राज्यों से आए 35 से 40 कोविड मरीजों का इलाज जारी है. बताया गया है कि ज्यादातर मरीजों को इस समय ऑक्सीजन की जरूरत है. ऐसे में कई लोग दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा से सीधे पंजाब का रुख कर रहे हैं. कोई अपने रिश्तेदारों के जरिए अस्पताल में बेड का इंतजाम करवा रहा है तो कोई सीधे किसी बड़े अस्पताल से संपर्क साध रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटियाला से कुछ किलोमीटर दूर, एक दंपति एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ा था, दावा करता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी माँ की मृत्यु हो गई. निजी अस्पताल बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं. दिल्ली और पंजाब के मरीज़ हैं. कभी-कभी वे दिल्ली के मरीजों को एडजस्ट करने के लिए स्थानीय लोगों की उपेक्षा करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है. हालांकि, आधी रात को अस्पताल ने लगभग एक दर्जन रोगियों को ट्रांसफर कर दिया.

कोविड मौतों का बढ़ रहा आंकड़ा, एमसीडी ने 9 शवदाह गृह पर बढ़ाए प्लेटफार्म

नई दिल्ली । दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है. सोमवार को पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई. वहीं, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,628 को पार कर गया है.

कोविड मौतों की बढ़ती संख्या के चलते दिल्ली नगर निगमों की ओर से श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों पर अंतिम संस्कार के लिए मौजूदा प्लेटफार्म में भी इजाफा किया जा रहा है. साउथ दिल्ली नगर निगम की ओर से कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़ रही मौतों के चलते अपने सभी 9 श्मशान घाट और कब्रिस्तान में अतिरिक्त प्लेटफार्म का प्रबंध किया है. एसडीएमसी की मेयर अनामिका ने कहा कि दक्षिणी निगम के सभी श्मशान घाटों में कोरोना मृतकों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफार्म की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. पहले कोविड शवों के लिए प्लेटफार्म की संख्या 289 थी जिसे बढ़ाकर 357 कर दिया गया है. आवश्यकता के अनुसार प्लेटफार्म की संख्या को बढ़ाया जाएगा. मेयर ने बताया कि दक्षिणी निगम के पंजाबी बाग, हस्तसाल, सुभाष नगर, लोधी रोड, सराय काले खान, लाल कुआं, आई.टी.ओ, द्वारका सेक्टर 24 और ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाटों व कब्रिस्तान में एक दिन में 357 कोरोना मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि दक्षिणी निगम के सराय काले खान श्मशान घाट की क्षमता को बढ़ाया गया है. घाट पर अतिरिक्त 20 अस्थाई प्लेटफार्म बनाए गए हैं जिसे आवश्यकतानुसार और अधिक बढ़ाया भी जा सकता है. मेयर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सभी श्मशान घाटों पर अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि अधिक शव आने पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा सके. इसके अतिरिक्त सभी श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में नियमित रूप से सेनेटाइजेशन और साफ-सफाई भी की जा रही है ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके.

दिल्ली में विदेशों से मंगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट और टैंकर : सीएम

नई दिल्ली । दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के कारण लगातार ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह बताया कि वह दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कैसे प्लान बना कर काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही बेड की हो रही कमी को देखते हुए आइसीयू बेड के बढ़ाने पर भी सरकार का एक्शन प्लान जनता के सामने रखा।

सीएम केजरीवाल मंगलवार को कोरोना को लेकर डिजिटल प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने दिल्लीवासियों को यह भरोसा दिलाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन बेड की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर आइसीयू बेड तैयार कर रही है। वहीं जीटीबी अस्पताल के सामने वाले राम लीला ग्राउंड में 500 आइसीयू बेड तैयार हो रहे हैं। 200 आइसीयू बेड राधा स्वामी सत्संग ब्यास में तैयार हो रहे हैं। कुल 1200 आइसीयू बेड 10 मई तक तैयार हो हो जाएंगे।

इसके साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए भी दिल्ली सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। मंगलवार को सीएम ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए दिल्ली सरकार बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर और फ्रांस से 21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवा रही है। केंद्र सरकार भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला कर देश के हर होने में ऑक्सीजन की

सप्लाई कर रही है। दिल्ली को भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस से करने की कोशिश हो रही है, ताकि राजधानी के हालात जल्द से जल्द सुधर सके। बीते कुछ दिनों में दिल्ली-सहित एनसीआर के कुछ इलाकों में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत की खबर देखने को मिल रही है।

बता दें कि इससे पहले सीएम ने देश के अन्य मुख्यमंत्रियों समेत टॉप उद्योगपतियों को चिट्ठी लिख कर ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही थी। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ राज्यों के साथ वार्ता सकारात्मक हो रही है। जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बीते कुछ दिनों से दिल्ली के कमोबेश हर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं।

केजरीवाल ने सभी मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों को शुक्रिया-

मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों को मदद के लिए चिट्ठी लिखी थी. हमें सभी से पूरा सहयोग मिल रहा है. मैं सभी मुख्यमंत्रियों, उद्योगपतियों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ.

पिछले 24 घंटों में 22,055 मरीज हुए ठीक- दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 22,055 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं और शहर में अब तक 9,40,930 लोग इस घातक बीमारी को मात दे चुके हैं. दिल्ली का रिकवरी रेट 89.79 फीसदी दर्ज किया गया है. वहीं, कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.40 प्रतिशत पर पहुंच गई है. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 57,690 कोरोना टेस्ट हुए हैं और राजधानी में अब तक 1,68,39,549 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 38,786 RT-PCR टेस्ट और 18,904 एंटीजन टेस्ट शामिल हैं.

मारपीट का बदला लेने के लिए कर दी थी हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली । गत शनिवार को भारत नगर इलाके में घोषित बदमाश राहुल की हत्या मारपीट का बदला देने के लिए की गई थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या में शामिल मोतिया उर्फ दीपक और मनोज को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार 24 अप्रैल को भारत नगर थाना क्षेत्र में राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी गई है। राहुल इसी थाने से घोषित बदमाश था। आरोपितों के लिए अपराध शाखा के एसीपी उदयवीर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रमेश लांबा की टीम ने वजीरपुर जेजे कालोनी से मोतिया उर्फ दीपक व मनोज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपितों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि राहुल ने मोतिया के दोस्त के साथ मारपीट की थी। इसके अलावा 18 अप्रैल को राहुल ने मोतिया के साथ भी मारपीट की थी। इस मामले में राहुल जेल भी गया था। फिलहाल, पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है।

हेरोइन के साथ दो गिरफ्तार- वहीं, बरेली, उत्तर प्रदेश से हेरोइन लाकर दिल्ली एनसीआर में बेचने वाले दो तस्करों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 270 ग्राम हेरोइन, एक स्कूटी, बाइक और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं दिया डाक्टरों व शिक्षकों को वेतन आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करें- हाई कोर्ट

नई दिल्ली । अदालत के आदेश के बावजूद भी नगर निगमों के डाक्टरों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पूरा वेतन व पेंशन नहीं जारी करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि अदालत ने पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया था। आपने भुगतान क्यों नहीं किया, अब आप बताएं कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाये। पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा कि क्यों न निगम आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाये और सम्पत्ति जब्त की जाये।

वेतन एवं पेंशन भुगतान को कर्मचारी संगठनों एवं कर्मचारियों की तरफ कई याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पीठ ने उक्त टिप्पणी तब की, जब एनडीएमसी के स्टैंडिंग काउंसल दिव्य प्रकाश पांडे ने पीठ को बताया कि डाक्टर, नर्स व मेडिकल स्टाफ का फरवरी माह तक वेतन जारी किया है, जबकि शिक्षकों व ग्रुप ए को जनवरी तक का भुगतान किया गया है।

हालांकि, अदालत के रुख पर निगम अधिवक्ता ने कहा कि हम बहाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन अचानक कोरोना की दूसरी लहर के कारण हमें पर्याप्त अनुदान नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकार भी वित्तीय संकट में है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को वेतन भुगतान के लिए बकाया 250 करोड़ रुपये देने की मांग को लेकर एक आवेदन दाखिल किया गया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं है।

पीठ ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए सुनवाई 31 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। वहीं, दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि वेतन का भुगतान करने के लिए नगर निगम अग्रिम भुगतान की मांग नहीं कर सकता है। वहीं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पीठ को बताया कि उन्होंने सभी कर्मचारियों का मार्च तक के वेतन एवं पेंशन का भुगतान कर दिया है। इससे पहले अदालत ने सभी नगर निगमों को पांच अप्रैल तक कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने वेतन भुगतान के लिए और समय देने की निगमों की मांग को ठुकरा दिया था।

रवि गुप्ता ने बताया कैसे मिली कोरोना से जीत, आप करें ये इस्तेमाल नहीं होंगे बीमार

नई दिल्ली । राजधानी में कोरोना महामारी के चलते हजारों लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक बीमारी से ग्रसित लोग अपने घरों में होम आइसोलेशन में रहकर इस महामारी से लड़ रहे हैं और आसानी से जंग जीत रहे हैं। पटेल नगर निवासी रवि गुप्ता भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, जो एक महीने पहले संक्रमित हुए थे। इसके बाद होम आइसोलेशन में रहकर सुबह-शाम घर के बने काढ़े का प्रयोग किया और बीमारी पर विजय प्राप्त की।

रवि गुप्ता ने बताया कि वे शुरुआत में कोरोना की रिपोर्ट पाजिटिव आने के बाद घबरा गए थे, लेकिन जब परिवार के सदस्यों ने उन्हें हौसला दिया और घर में रहकर ही उपचार लेने की सलाह दी तो बीमारी से लड़ना आसान हो गया। उन्होंने घर की छत पर बने कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर लिया, जिसमें काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ, गुड़, लौंग आदि औषधि मिलाकर काढ़ा बनाया, जिसका सुबह और शाम को लगातार सेवन किया। इससे बुखार होने पर भी आराम मिला और गले का दर्द भी जल्द खत्म हो गया। परिवार के सदस्य खाना देने के लिए आते थे, जो दूर रखकर चले जाते थे। उनसे वीडियो काल कर बात करता था।

एक कोविड-19 पीड़िता के रिश्तेदार नई दिल्ली के गाजीपुर श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करते हुए।

यूपी-दिल्ली और हरियाणा के किसानों के लिए राहत की खबर, पराली जलाने पर अब नहीं होगी जेल

नई दिल्ली । पराली जलाकर दिल्ली-एनसीआर की हवा प्रदूषित करने वाले किसानों को अब जेल नहीं होगी। यही नहीं, उन पर एक करोड़ रुपये तक के मोटे जुर्माने का प्रविधान भी खत्म कर दिया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का पुनर्गठन कर इस आशय की नई अधिसूचना से उक्त दोनों ही प्रविधान हटा लिए हैं। इसके अलावा आयोग में एक सदस्य कृषि क्षेत्र से भी शामिल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि जब अक्टूबर 2020 में 18 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था तो आयोग को पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए थे। इनमें दोषी किसानों पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने और पांच साल तक के लिए जेल भेजने का प्रविधान भी था। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों की मांगों में एक मांग यह प्रविधान हटाने की भी थी। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान भवन में बैठक हुई, तब भी इस मांग पर प्रमुखता से जोर दिया गया था। इसी के मददेनजर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन से जुड़ी अन्य मांगों के साथ किसानों की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना के जरिये ही गठित किया गया यह आयोग 12 मार्च 2021 को भंग हो गया था। वजह यह थी कि सरकार इस आशय का विधेयक संसद में पेश नहीं कर पाई। लेकिन ऐंसा सोची समझी रणनीति के तहत ही किया गया था।

दरअसल, कैबिनेट में पास पूर्व विधेयक में से उक्त प्रविधान हटाने के लिए विधेयक नए सिरे से तैयार कर कैबिनेट में लाया जाना था। इसीलिए इसे भंग करके नए सिरे से पुनर्गठित करने की योजना बनाई गई। अब आयोग के पुनर्गठन के नए विधेयक को कुछ बदलावों के साथ कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसीलिए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मानसून सत्र में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया जाएगा।केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा 13 अप्रैल को जारी अधिसूचना के क्रम में 23 अप्रैल को इसके 18 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके हैं तब भी बरतें सावधानी, हो सकते हैं संक्रमित

नई दिल्ली। टीके के दोनों डोज लगवाने के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर आश्वस्त होने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि टीके लगवाने के महीनों बाद भी कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी जद में ले रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि टीका प्राप्त लोग होम आइसोलेशन में रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में अतिरिक्त निदेशक शैक्षणिक प्रो. डा. भरत भोयार ने बताया कि 27 फरवरी को उन्होंने टीके का दूसरा डोज लगवाया था। पर दस अप्रैल को उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पाजीटिव आई, जिसके बाद से वे होम आइसोलेशन में है और फिलहाल पूरी तरह स्वस्थ है।

अपना अनुभव साझा करते हुए डा. भरत बताते हैं कि रिपोर्ट पाजीटिव आने के बाद एक पल को मन में डर का माहौल बन गया, क्योंकि मुझे तेज बुखार, खांसी-जुकाम, गले में बलगम जैसी समस्या थी। बढ़ते संक्रमण दर व मृत्युदर को देखकर डर लगना स्वाभाविक है। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आयुर्वेदिक व एलोपेथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज शुरू किया। फिलहाल मुझे हल्की खांसी व जुकाम है, जिसके लिए मैं चिकित्सीय परामर्श अनुसार दवाई ले रहा हूं।

द्वारका सेक्टर-18 निवासी डा. भरत बताते हैं इस संकट की घड़ी में अधिकांश कोरोना संक्रमित घरों में आइसोलेट है और यदि वे नियम का ठीक ढंग से पालन सुनिश्चित करें तो वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते है। अपनी दिनचर्या का जिक्र करते हुए डा. भरत बताते हैं कि मैं परिवार से अलग एक कमरे में अकेले रह रहा हूं और अलग शौचालय का प्रयोग कर रहा हूं। परिवार का कोई सदस्य मेरे कमरे में प्रवेश न करें, इसके लिए सभी को सख्त आदेश दिया गया है। खाने में पौष्टिक आहार का सेवन कर रहा हूं। इसके अलावा मौसमी फलों जैसे तरबूज, सेब, खरबूजा आदि को अधिक से अधिक खाने में शामिल किया है। डा. भरत बताते है इस समय निर्जलीकरण की समस्या न हो यह बेहद जरूरी है।

इसलिए रसदार फलों के साथ गुनगुने पानी का ज्यादा सेवन कर रहा हूं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध काफी अहम है। डा. भरत बताते हैं कि वे नियमित रूप से आक्सीजन व रक्तचाप स्तर माप रहे है, ताकि समस्या होने पर समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए टीवी और मोबाइल पर समय व्यतीत करने के साथ योग व प्राणायाम की मदद ले रहा हूं। कोरोना संक्रमण को मात देने में योग व प्राणायाम का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जहां तक दवा की बात है प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए गिलोए घनवटी और अश्वगंधा का सेवन कर रहा हूं। कमरे में अकेले रहने के बावजूद हर समय मास्क लगाता हूं और प्रत्येक आठ घंटे में मास्क को बदल लेता हूं। मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए निगम की गाड़ी नियमित रूप से आ रही है। जहां तक साफ-सफाई की बात है उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है।

आइनाक्स ने कहा आपूर्ति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के आदेश में है विरोधाभास

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आक्सीजन की किल्लत पर हर तरफ से उठ रहे सवालों के बीच आइनाक्स के निदेशक सिद्धार्थ जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि देशभर में 800 अस्पतालों में आक्सीजन आपूर्ति की जा रही है, लेकिन शिकायत सिर्फ दिल्ली से है। उन्होंने कहा कि यह तब हो रहा जब दिल्ली की उनकी आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा कम कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली का आवंटन कम कर दिया गया है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण सभी टैंकर वहां जा रहे हैं। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष सिद्धार्थ जैन ने बताया कि दिल्ली को पहले 105 टन आक्सीजन आवंटित किया गया था, जिसमें बाद में घटाकर 80 टन कर दिया गया। इसके अलावा उन्हें 80 टन आक्सीजन पानीपन से ट्रांसपोर्ट करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली सरकार और केंद्र से मिलने वाले आदेश में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल को 125 टन आक्सीजन अस्पतालों को आपूर्ति करने का आदेश जारी किया, जबकि केंद्र सरकार ने आवंटन रिवाइज करते हुए दिल्ली को 80 टन आक्सीजन आवंटित करने का आदेश जारी किया। आखिर हम क्या करें। उन्होंने कहा कि आवंटित 490 टन में से दिल्ली को 300 टन ही मिला। आपूर्ति की कमी के कारण अस्पताल से हमें लगातार फोन आ रहे हैं, हम सात दिन से सोये नहीं हैं। उन्होंने पीठ से कहा कि हमें निर्देश दीजिए हमें किस अस्पताल को कितनी आपूर्ति करना है। उन्होंने कहा कि उनके आधे कर्मचारियों को कोरोना हुआ है और डाटा भेजने के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। हमारे टैंकर रोक लिए कैसे करें आपूर्ति पीठ ने सुनवाई के दौरान आइनाक्स से कहा आपके पास कई टैंकर हैं।

एक साल के दौरान कैसे दिल्ली मेट्रो को हुआ 3000 करोड़ रुपये का घाटा

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में 19 अप्रैल से जारी लॉकडाउन ने न केवल बाजार और रोजगार को प्रभावित किया है, बल्कि इससे दिल्ली मेट्रो रेल निगम को भी भारी नुकसान हो रहा है। 3000 करोड़ रुपये से अधिक के घाटे के साथ चल रही दिल्ली मेट्रो अब लॉकडाउन के कारण और भी बेहद कम क्षमता के यात्रियों के साथ दिल्ली-एनसीआर में दौड़ रही है। मार्च 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण से पहले दिल्ली मेट्रो की रोजाना कमाई 10 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसके बाद लगातार 6 महीने तक बंद रही। सितंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली मेट्रो का संचालन तो शुरू हुआ, लेकिन कम यात्रियों की क्षमता के साथ, जो अब तक जारी है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो के घाटे को लेकर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है।

लॉकडाउन ने दिया बड़ा झटका

अब तक दिल्ली मेट्रो बेहद कम

झमता के साथ रफ्तार भर रही थी, लेकिन 19 अप्रैल से दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन ने तो उसे फिर से आर्थिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में आगामी 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन को देखते हुए मेट्रो सेवाओं में कटौती की गई है। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवा रोजाना की तरह नहीं रहेगी। इस दौरान सुबह और शाम के वक्त आधे घंटे के अंतराल और बाकी समय में एक घंटे के अंतराल पर चलेगी। इतना ही नहीं, 3 मई तक दिल्ली मेट्रो सभी रूटों पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के अंतराल पर चलाई जा रही है। वहीं बाकी समय के बीच मेट्रो सेवा एक घंटे के अंतराल पर चल रही है। दिल्ली मेट्रो की ओर से यह बताया गया है कि सभी रूट पर इसी टाइम पर मेट्रो सेवा चालू रहेगी। लॉकडाउन के दौरान जिनको सफर करने की छूट है वही यात्री सफर कर सकेंगे। जाहिर है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सी कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद है। इससे आवागमन बंद है और जो आवाजाही कर भी रहे हैं, उनकी संख्या बेहद कम है।

बता दें कि पहले मार्च से अगस्त के दौरान कोरोना महामारी के चलते लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मेट्रो परिचालन बंद होने से डीएमआरसी को मार्च, 2020 से अगस्त 2020 तक 1500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। डीएमआरसी के अनुसार, कोरोना काल के चलते दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से 7 सितंबर तक बंद रही। इस दौरान डीएमआरसी को 1600 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके बाद जब से मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ इसके बाद भी लोग मेट्रो में पहले की तरफ यात्रा करने से बच रहे हैं।

सितंबर से अब तक हो चुका है 1500 करोड़ रुपये का नुकसान

अनलॉक के दौरान सितंबर के पहले सप्ताह से दिल्ली मेट्रो चरणबद्ध तरीके से शुरू तो हुई, लेकिन बेहद कम यात्री संख्या के साथ। इसके बाद सितंबर से लेकर जनवरी 2021 तक ही दिल्ली मेट्रो को 1,200 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा था।

खर्च बढ़ा, लेकिन कमाई घटी

कोरोना वायरस संक्रमण और खतरे के चलते सैनेटाइजर, साफ-सफाई के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए अन्य मद में भी डीएमआरसी का खर्च बढ़ा है। इससे दिल्ली मेट्रो के संचालन की लागत भी बढ़ गई है, लेकिन कमाई में इजाफा नहीं हुआ है।

लॉकडाउन से पहले 10 करोड़ रुपये रोजाना थी डीएमआरसी की कमाई- लॉकडाउन के पहले यानी मार्च, 2020 से पहले दिल्ली मेट्रो हर दिन तकरीबन 10 करोड़ रुपये का राजस्व जुटा रही थी। यहां तककि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर शाहीन बाग में तकरीबन 3 महीने तक आंदोलन के दौरान दिल्ली मेट्रो की यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ था। इस दौरान कमाई भी बढ़ी थी। इस दौरान कभी-कभार दिल्ली मेट्रो यात्रियों की संख्या 50 लाख से ऊपर तक पहुंच गई थी। इस अनुपात में कमाई भी बढ़ी थी। आंकड़ों के मुताबिक, कोविड-19 महामारी से पहले रोजाना करीब 62 लाख यात्री दिल्ली मेट्रो में सफर करते थे, लेकिन अब यह संख्या अब कई गुना घट गई है।

संपादकीय

पृथ्वी के लिए चाहिए नया नजरिया

पर्यावरण-संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सन 1972 में दुनिया भर के नेतागण स्टॉकहोम में एकत्र हुए थे। तब चिंताएं स्थानीय पर्यावरण को लेकर थीं। जलवायु परिवर्तन या फिर छीज रहे ओजोन परत पर उस बैठक में कोई बात नहीं की गई थी। ये सभी मसले बाद के वर्षों में शामिल किए गए हैं। सन 1972 में तो सिर्फ जहरीले होते पर्यावरण को तवज्जो मिली थी, क्योंकि पानी और हवा दूषित हो चले थे। यहां बेशक कोई यह कह सकता है कि पिछले पांच दशकों में काफी कुछ बदल गया है। मगर असलियत में हालात जस के तस हैं। या यूं कहें कि स्थिति गंभीर ही बनती जा रही है। पृथ्वी के तमाम घटकों का दूषित हो जाना, आज भी चिंता की एक बड़ी वजह है। कुछ देशों ने हालात संभालने के लिए स्थानीय स्तर पर कई कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन वैश्विक पर्यावरण में उनका उत्सर्जन बदस्तूर जारी है। अब तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकना हमारे बस से बाहर की बात हो चली है, और वक्त पल-पल रेत की मानिंद हमारे हाथों से फिसल रहा है। यही कारण है कि हम आज दुनिया को काफी तेजी से असमान होते देख रहे हैं। यहां गरीबों व वंचितों की तादाद बढ़ती जा रही है, और जलवायु परिवर्तन के जोखिम गरीबों के घर ही नहीं, अमीरों के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। इसीलिए पुरानी रवायतों को विदा करने का वक्त आ गया है। साझा भविष्य के लिए हमें न सिर्फ अपनी कार्यशैली, बल्कि अपना नजरिया भी बदलना होगा।

अगले साल हम स्टॉकहोम सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसके 'कन्वेंशन' को अब अलग रूप देना होगा। इसमें महज समस्या की चर्चा न हो, बल्कि समाधान के रास्ते भी बताए जाएं। इसीलिए हमें उपभोग और उत्पादन पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। इसे हम और नजरंदाज नहीं कर सकते। यह बहस-मुबाहिसों में ज्वलंत मसला है। हम ओजोन, जलवायु और जैव-विविधता से लेकर मरुस्थलीकरण व जहरीले कचरे के बारे में तमाम तरह के समझौते करके वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की जब वकालत करते हैं, तब एकमात्र तथ्य यही समझ में आता है कि तमाम देशों ने अपनी सीमा से कहीं अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वैश्विकता में और एक-दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां सभी देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं। मगर इस दरम्यान तो हमने एक अन्य मुक्त व्यापार समझौता किया, आर्थिक वैश्वीकरण समझौता। हम दरअसल, यह समझ ही नहीं पाए कि ये दोनों फ्रेमवर्क (पारिस्थितिकी और आर्थिक वैश्वीकरण) एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं। लिहाजा, अब हमें एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना होगा, जिसमें श्रम मूल्य और पर्यावरण, दोनों को बराबर तवज्जो मिले। हमने वहां-वहां उत्पादन बढ़ाए हैं, जहां लागत सस्ती है। उत्पादन बढ़ाने का हमारा एकमात्र मकसद यही है कि हमारे भंडार भरे रहें। इससे उत्पाद कहीं ज्यादा सस्ता और सुलभ भी हो जाता है। सभी देश विकास के इसी मॉडल को अपना रहे हैं। हर कोई वैश्विक कारखानों का हिस्सा बनना चाहता है, जहां हरसंभव सस्ते दामों में उत्पादन संभव है। दुनिया का गरीब से गरीब देश भी यही चाहता है कि वह जल्द से जल्द संपन्न बन जाए, और उत्पादों का अधिकाधिक उत्पादन व खपत करे। मगर इसकी कीमत पर्यावरण सुरक्षा के उपायों की अनदेखी और श्रम की बदहाली के रूप में चुकाई जाती है।

कोविड-19 महामारी ने इस 'अनियंत्रित विकास-यात्रा' को रोक दिया है। यह ऐसी यात्रा रही है, जिसमें कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन और उनके हरसंभव उपभोग पर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि पृथ्वी खुद अपने नियम तय करती है और उसके पास चीजों को अलग तरीके से करने का विकल्प होता है। कोविड-19 भी हमें यही संदेश देता प्रतीत हुआ है। इसके कुछ सबक हमें कतई नहीं भूलने चाहिए। पहला, हमें श्रम, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों का मोल समझना होगा। उद्योग जगत के लिए आज यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हमने देखा है कि पिछले साल अपने देश में किस तरह से गांवों की ओर श्रमिकों की वापसी हुई। आज भी जब दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा की गई, तब देशव्यापी लॉकडाउन की आशंका में कामगारों की फौज गांवों की ओर निकल पड़ी है। हालांकि, यह संकट भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में है। इससे उत्पादन खासा प्रभावित होता है। इसी कारण पिछले साल जब संक्रमण के हालात संभलते दिखे, तब कंपनियां अपने श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए उनकी चिरौरी करती दिखीं। श्रमिकों को अच्छा वेतन और बेहतर कामकाजी माहौल देने की आवश्यकता है। दूसरा सबक, हम आज नीले आसमान और स्वस्थ फेफड़े की कीमत समझने लगे हैं। लॉकडाउन के दरम्यान प्रदूषण का स्तर सुधर गया था। इसे हमें लगातार महत्व देना होगा। साफ-सुथरी आबोहवा के लिए यदि हम निवेश करते हैं, तो निश्चय ही उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तीसरा, भूमि-कृषि-जल प्रणालियों में निवेश के मूल्य को हमें समझना होगा। जो लोग अपने गांवों में वापस जाते हैं, उन्हें वहां आजीविका की जरूरत भी होती है। हमें अब ऐसा भविष्य बनाना होगा, जिसमें खाद्य-उत्पादन तंत्र टिकाऊ, प्रकृति के अनुकूल और सेहत के माकूल हों। चौथा सबक, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, जिसमें 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से कामकाज सामान्य हो गया है। इस तरह की व्यवस्था आगे भी बनानी होगी, ताकि सुदूर इलाकों से कामकाज हो सके, यात्रा का तनाव कम हो और खुद को मजबूत करने के लिए हम देश-दुनिया से तालमेल बिठा सकें। पांचवां, तमाम सरकारें अपनी-अपनी आर्थिक मुश्कलों से लड़ रही हैं। इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने और कम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी आर्थिकी अपनानी होगी, जिसमें कचरे से भी संसाधन तैयार किए जा सकें। ये तमाम उपाय उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, आज कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तब हमें यही संकल्प लेना होगा कि इंसानी गतिविधियां पर्यावरण को दुष्प्रभावित न कर सकें। अब इस पर विचार-विमर्श करने का वक्त नहीं रहा। जरूरत युद्धस्तर पर काम करने की है।

प्रवीण कुमार सिंह

लॉकडाउन के अन्य विकल्पों को अमल में लाने से बचाव के साथ बनी रह सकती है अर्थव्यवस्था की रफ्तार

> ऐसे में सरकार को चाहिए कि सुशासन की सुसंगत व्यवस्था के लिए बढ़ी हुई ताकत से कोरोना से निपटे और आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए कोई जमीनी रणनीति भी सुझाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समग्र लॉकडाउन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, मगर रणनीति कब बदल जाएगी यह तो समस्या की गंभीरता के हिसाब से तय हो सकता है। देखा जाए तो कोरोना और कर्फ्यू सुशासन को चुनौती दे रहे हैं। सुशासन को चाहिए कि इनका देश निकाला करे, ताकि लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों को राहत मिले।

वर्तमान समय की वास्तविक उपलब्धि क्या है? इसका जवाब आसानी से नहीं मिलेगा, मगर दो टूक यह है कि इसका उत्तर कोरोना से मुक्ति है। देश में कोविड का संक्रमण पहली लहर की तुलना में इस बार काफी तेजी से फैल रहा है। पिछले लगभग एक सप्ताह से प्रत्येक दिन डेढ़ लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। मार्च के अंत में जहां एक्टिव केस भारत में एक लाख से कम थे, वहीं अब यह 14 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार के व्यापक कदम की सूचना नहीं है, मगर राज्यों ने अपने स्तर से लॉकडाउन और कर्फ्यू की ओर कदम बढ़ा दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर क्या होगा, इसके नियम तय किए जाने लगे हैं। शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है।

गौरतलब है कि जब पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर को डोल रही थी, तब भारत पहली लहर को आसानी से निपटाने में कामयाब होता दिख रहा था, मगर अब दूसरी लहर की स्थिति तो मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। कोरोना कब जाएगा, कितनी कीमत लेकर जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। एक ओर जहां भारत में टीकाकरण तेजी लिए हुए है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना पीड़ितों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी न केवल चिंता को बढ़ाने वाला है, बल्कि देश को नई बर्बादी की ओर भी धकेल रहा है।

ऐसे में सवाल शासन पर भी उठ रहा है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कोरोना से निपटने के मामले में सरकार की नीतियों को असफल बता रही हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के टीके की मांग और आपूर्ति में भी असंतुलन देखा जा रहा है। कई राज्यों से कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरें भी आ रही हैं। कई टीका केंद्र वैक्सीन के अभाव में तालाबंदी के शिकार हो गए हैं और ऐसी

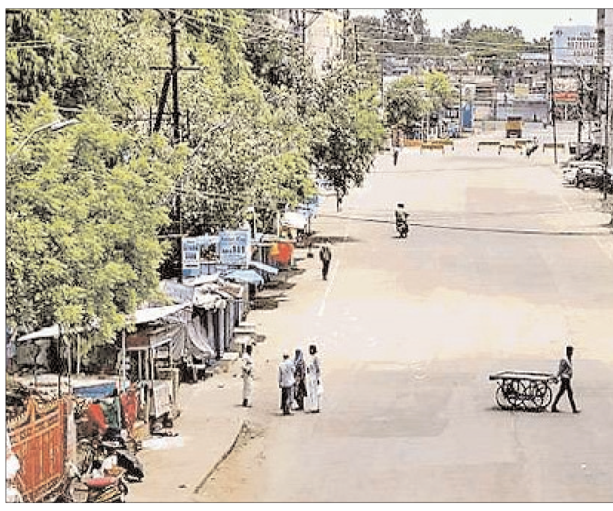

सूचनाएं महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों से हैं। हालांकि केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी को नकारते हुए इसे राजनीति बता रही है।

यदि वास्तव में वैक्सीन की कमी हो रही है तो यह चिंताजनक है, क्योंकि एक ओर जहां 11 से 14 अप्रैल के बीच 'टीका उत्सव' मनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर टीके की कमी शासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल देश में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से हमें एक नई राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत के कई राज्य नाइट कफ्यरू और लॉकडाउन के आंशिक असर से इन दिनों दो-चार हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा आदि शामिल हैं। इस प्रकार के निर्णय से यह बात आसानी से समझ में आती है कि सरकारों के पास रात में कर्फ्यू और सप्ताहांत लॉकडाउन के अलावा कोई और सरल तरीका शायद नहीं है। हालांकि ऐसे तरीकों को पहले भी प्रयोग में लाया गया था।

जाहिर है कोरोना चेन तोड़ने में कमोबेश यह मददगार सिद्ध हुआ होगा। मगर इसकी अपनी कई जटिलताएं हैं जिन पर अभी समग्र शोध किया जाना शेष है। इन दिनों लगभग पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रही है। ऐसे में इटली, पोलैंड, फ्रांस, हंगरी, बेल्जियम, ब्राजील समेत मध्य एशिया और अमेरिकी देशों में सप्ताहांत लॉकडाउन और कफ्यरू का प्रयोग देखा जा रहा है। फ्रांस में तो देशव्यापी लॉकडाउन का एलान भी किया जा चुका है, जबकि फिलीपींस जैसे देश आंशिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं।

कोरोना से बिगड़ती स्थिति को संभालने में क्या वाकई हमारी केंद्र सरकार विफल दिख रही है, जैसाकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं या फिर राज्यों ने स्थिति को समझने में कोई चूक की या जनता इसकी भयावह स्थिति से अनभिज्ञ रही। जो भी हो देश बड़ा है और कोरोना से निपटने में हमें काफी संजीदगी दिखानी होगी। मुंह पर मास्क और दो गज की दूरी लोगों से दूर हो जाना कतई उचित नहीं है। हालांकि जिस तरह बिहार चुनाव से मौजूदा समय में जारी चुनावी रैलियों में इस नियम का उल्लंघन दिखा, उससे भी जन मानस को ऐसा करने का बल मिलता है। इन दिनों इस मामले में प्रशासन भी सख्त है और बड़े पैमाने पर चालान काटे जा रहे हैं, पर यह समस्या का पूरा समाधान नहीं है। जाहिर है, इसे लेकर जनता को स्वयं जागरूक होना होगा।

एक ओर टीकाकरण का लगातार बढ़ना और दूसरी ओर कोरोना के ग्राफ का ऊंचा होना, शासन और जनता दोनों के लिए किसी संकट से कम नहीं है। शासन करने वाले मजबूत इच्छाशक्ति के होते हैं और उनमें जनता की ताकत होती है जिसका उपयोग जन सुरक्षा और लोक विकास में किया जाता है। मगर इस महामारी ने दोनों को खतरे में डाल दिया। बीते कुछ वर्षों से देश सुशासन की राह पर तेजी से दौड़ लगा रहा था। हालांकि आर्थिक संकट और बेरोजगारी से देश परेशान भी था और रही-सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। नतीजन एक बहुत बड़े जन मानस के समक्ष रोटी की समस्या खड़ी हो गई। सुशासन सामाजिक-आर्थिक न्याय है, लोकतंत्र की पूंजी है और सभी के लिए सवरेदय का काम करता है, मगर इन दिनों यह भी संकट से जूझ रहा है। पहली लहर में मध्यम वर्ग की कमर टूट गई थी, इस बार वह छिन्न-भिन्न हो सकता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सुशासन की सुसंगत व्यवस्था के लिए बढ़ी हुई ताकत से कोरोना से निपटे और आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए कोई जमीनी रणनीति भी सुझाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में समग्र लॉकडाउन को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है, मगर रणनीति कब बदल जाएगी यह तो समस्या की गंभीरता के हिसाब से तय हो सकता है। देखा जाए तो कोरोना और कर्फ्यू सुशासन को चुनौती दे रहे हैं। सुशासन को चाहिए कि इनका देश निकाला करे, ताकि लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों को राहत मिले।

अनाज ही नहीं, टीका भी मिले मुफ्त

देश के करीब 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले दो महीने यानी मई और जून में पांच-पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। भले ही इस बार देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया गया हो, लेकिन जैसे-जैसे महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तमाम राज्य सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे बहुत से लोगों के रोजी-रोजगार या तो छिन रहे हैं या छिनने के आसार बन रहे हैं। इसी वजह से प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा एक बार फिर अपने अपने गांवों की ओर लौट रहा है। ऐसे में इस तरह के कदम वक्त की जरूरत बन गए हैं। इसी बीच वैक्सीन का दायरा बढ़ाने की भी पहल हुई है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इससे जुड़े कुछ पहलुओं की आलोचना भी हो रही है।

खासकर वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों को लेकर। केंद्र सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन 150 रुपये प्रति डोज, राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति डोज और निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति डोज उपलब्ध कराए जाने की बात है। सीरम ने कोविशील्ड के लिए 600 रुपये की जो कीमत तय की है, वह अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे अमीर देशों की तुलना में अधिक है। कंपनी ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि 600 रुपये की कीमत निजी अस्पतालों के लिए है। इसकी तुलना अमीर देशों की सरकारों से ली गई कीमत से नहीं की जा सकती। और उन देशों से वैक्सीन बनाने के लिए उसे पहले ही फंडिंग मिल चुकी थी।

अब भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन के लिए राज्यों से 600 और निजी अस्पतालों से 1,200 रुपये लेने की बात कही है, जबकि केंद्र को वह पहले की तरह 150 रुपये पर इसकी सप्लाई करता रहेगा। राज्यों और निजी अस्पतालों के लिए ऊंची कीमत रखने पर भारत बायोटेक की भी आलोचना हो रही है। असल में कुछ जानकारों का कहना है कि टीके की ऊंची कीमत से टीकाकरण अभियान में कुछ दिक्कत हो सकती है। विपक्ष भी टीके की कीमतों पर केंद्र की नीति को भेदभावपूर्ण बता रहा है। इसके साथ पूरी आबादी को मुफ्त टीका दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। सच यह भी है कि बीजेपी समेत विपक्ष शासित कई राज्यों ने अपने यहां लोगों को मुफ्त टीका देने का वादा किया है।

मुफ्त टीके की हिमायत में कुछ गैर-राजनीतिक संगठन पल्स पोलियो अभियान की मिसाल दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पोलियो का टीका मुफ्त नहीं दिया जाता, तो यह सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक स्टडी में यह भी बताया गया कि 18 साल से ऊपर की समूची आबादी को मुफ्त टीका लगाने का खर्च भी करीब 67 हजार करोड़ रुपये ही आएगा, जो जीडीपी का 0.36 फीसदी ही बैठता है। केंद्र चाहे तो राज्यों के साथ इस खर्च को बांट सकता है। आखिर मौजूदा नीति में भी दोनों ही टीकाकरण का खर्च उठा रहे हैं। यानी जरूरत है तो दोनों के बीच बेहतर तालमेल और केंद्रीय स्तर पर इसकी पहल की।

देश में कॉरपोरेट टैक्स प्रणाली में बदलाव की तैयारी, विदेशी निवेश बढ़ने की आस

भारत के पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय बजट में घोषणा की थी कि जो कंपनियां कॉरपोरेट कर में छूट नहीं लेंगी, उन पर कर की दर 30 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत ही होगी। गौरतलब है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्व सरकारों ने भारी मात्र में करों में छूट का प्रविधान रखा हुआ था। ऐसे में हालांकि कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत होने के बावजूद इसकी प्रभावी दर 23 प्रतिशत से ज्यादा नहीं थी। लिहाजा टैक्स को 25 प्रतिशत करने पर भी सरकार को नुकसान नहीं था। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि ऐसे में भारत 30 प्रतिशत और अधिक कॉरपोरेट टैक्स के देशों की सूची में से निकल कर कम टैक्स की श्रेणी में आ गया। यह कदम निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाला माना गया। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा कर दी कि जो पुरानी कंपनियां छूट नहीं लेंगी, उन्हें मात्र 22 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होगा और नई कंपनियों को तो मात्र 15 प्रतिशत की दर से ही कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। गौरतलब है कि इस टैक्स पर 10 प्रतिशत सरचार्ज और चार प्रतिशत स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेस लगता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के बारे में यह धारणा रही है कि यहां कॉरपोरेट टैक्स की दर बहुत अधिक है, जिसके चलते भारत में निवेशक कम आकर्षित होते हैं। वास्तव में यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले भारत के प्रतिस्पर्धी देशों में कॉरपोरेट टैक्स की दर भारत से कम थी। देखा जाए तो सिंगापुर में यह दर 17 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 25 प्रतिशत, वियतनाम में 20 प्रतिशत, अमेरिका में 21 प्रतिशत और हालांकि चीन में यह 25 प्रतिशत है, लेकिन हाईटेक उद्योगों में यह मात्र 15 प्रतिशत ही है। यानी भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाना इसलिए औचित्यपूर्ण दिखा, क्योंकि अन्य देशों में यह भारत से काफी कम था।

यह दर घटाने से अब भारत दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स लगाने वाले देशों में शामिल हो गया। वास्तव में पिछले कुछ समय से विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की होड़ के कारण कॉरपोरेट टैक्स दरों को घटाने का सिलसिला कुछ समय से चल रहा है। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने के साथ निजी आय पर कर की दरें बदस्तूर जारी रही। आज भी भारत में आयकर की सीमांत दर 30 प्रतिशत बनी हुई है। इसके साथ ही इस आयकर पर सरचार्ज भी लगाया जाता है।

गौरतलब है कि सरकारी खर्च का बहुत कम हिस्सा ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला विकास, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास समेत सामाजिक सेवाओं के लिए उपलब्ध होता है। पिछले बजटों में यह कुल सरकारी खर्च का महज 10 प्रतिशत ही रहा। इसी प्रकार देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी भारी खर्च करने की जरूरत होती है, ताकि भविष्य में विकास की राह आसान हो सके। लेकिन धनाभाव में सरकार चाहकर भी अधिक धन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं कर पाती। लेकिन यदि सरकारी राजस्व ही कम होगा तो सरकार इन मदों पर खर्च कैसे बढ़ाएगी, यह समझ के परे है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉरपोरेट पर कर कम करने से न तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है, न ही सरकार को, इससे सिर्फ कंपनियों के कर उपरांत लाभ बढ़ जाते हैं और कंपनियों के धनाढ्य स्वामियों की संपत्ति बढ़ती चली जाती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कंपनियों के पास ज्यादा पैसा होने पर वे निवेश बढ़ाएंगी, लेकिन पिछले 10 वर्षों का अनुभव यह बता रहा है कि आज कंपनियों के पास अकूत संपत्ति होने के बावजूद वे निवेश बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में अमीर लोग देश छोड़ विदेशों में अपनी संपत्ति स्थानांतरित कर रहे हैं। यह अत्यधिक चिंता का विषय है।

हालांकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉरपोरेट टैक्स को घटाया था, नए राष्ट्रपति जो बाइडन को सरकार की उस गलती का अहसास हो गया और उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को 21 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की है। लेकिन दुनिया में जहां देशों के बीच निवेश प्राप्त करने की जल्दबाजी के चलते प्रतिस्पर्धी रूप से कॉरपोरेट टैक्स को घटाने की होड़ लगी हुई है, अमेरिका को यह भी डर लग रहा है कि कहीं इससे निवेशक अमेरिका से बाहर न हो जाएं। हालांकि अमरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यह कह तो रहे हैं कि कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन साथ ही उनकी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास करने में जुट गई है कि पिछले 30 वर्षो से चल रही कॉरपोरेट टैक्स घटाने की इस प्रतिस्पर्धा पर विराम लग सके। अमेरिका की राजस्व सचिव जैनेट येलेन ने हाल ही में कहा है कि वे जी-20 देशों के समूह के साथ बातचीत कर रही हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम कॉरपोरेट टैक्स के बारे में सहमति बन सके। अमेरिका के इस प्रयास में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि केवल टैक्स दर घटाकर निवेश प्राप्त करने की ये कोशिशें सामाजिक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को प्रभावित कर रही हैं, जिससे आम जनता और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने का यह प्रयास दो खरब डॉलर की महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जरूरत इस बात की है कि एक स्थायी कर व्यवस्था बने, जिससे सरकारों को राजस्व की कमी न रहे और आवश्यक सामाजिक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कोई बाधा न हो।

माओवादी नेता नामी बेनामी संपत्ति के साथ गांजा-अफीम की खेती और तस्करी से इकट्ठा कर रहे अकूत धन

> गांजा-अफीम की खेती और तस्करी से इन्हें अकूत धन प्राप्त हो रहा है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर माओवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले अधिकतर जवान गांवों के गरीब किसानों और मजदूरों की ही संतानें हैं। साफ है कि माओवादियों से लड़ाई में जो खून बह रहा है वह भी गरीब का ही खून है। गरीब-गरीब को लड़ाकर माओ के वंशज भारत को न केवल सीमा पर, बल्कि देश के अंदर अघोषित युद्ध छेड़कर देश के विकास को रोकना चाहते हैं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर माओवादियों की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि नक्सली वस्तुत॰ माओवादी ही हैं। ये चीन-पाकिस्तान के दलाल भी बन गए हैं। इन्हें नेस्तनाबूद किया ही जाना चाहिए। माओवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा समय की मांग है।

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर माओवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। माओवादियों ने उन पर आधुनिक हथियारों से आक्रमण किया। विगत एक दशक में केवल छत्तीसगढ़ में ही हमारे सैकड़ों जवानों ने अपनी जान गंवाई है। वर्ष 1967 में बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद वहां जो सरकार बनी उसमें माकपा भी साझेदार थी। चारु मजूमदार माकपा के ही कार्यकर्ता थे। माकपा नेता के नाते वह उत्तर बंगाल में खेतिहर मजदूरों के बीच जाकर आर्थिक और सामाजिक शोषण करने वाले भूमिपतियों को वर्गशत्रु घोषित कर उनके 'खात्मे' की घोषणा किया करते थे।

'जो जमीन को जोते बोये-वह उसका मालिक होये'-इस नारे को साकार करने के लिए चारु मजूमदार के कहने पर सरकार बनने के अगले दिन यानी तीन मार्च, 1967 को धनुष-बाण और परंपरागत हथियारों के साथ आदिवासियों ने जमीन के एक टुकड़े पर लाल झंडा गाड़कर कब्जा कर लिया। 23 मई, 1967 को जब पुलिस उस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने गई तो उस पर आक्रमण हुआ, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर वांगड़ी घायल हुए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। फिर 25 मई, 1967 को पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई। हमला होने पर पुलिस की गोली से 10 लोग मारे गए। यह सारी घटना नक्सलबाड़ी गांव में घटी। अत॰ इसका नाम 'नक्सल आंदोलन' और आंदोलनकारियों को 'नक्सली' कहा जाने लगा। जिस नक्सल आंदोलन की देश में चर्चा होती है, उसके संस्थापक चारु मजूमदार ने खेतिहर किसान-

मजदूरों के छापामार युद्ध की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने परंपरागत हथियारों यानी फरसा, खुखरी, हसुआ, तलवार, भाला, धनुष-बाण आदि के माध्यम से वर्ग शत्रु के खात्मे की बात कही थी। 1970 के मई महीने में पार्टी कांग्रेस में उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर हम परंपरागत हथियार के सहारे वर्ग शत्रु के खिलाफ युद्ध छेड़ते है तो आम नागरिक विशेषकर भूमिहीन और गरीब तबका हमारे संघर्ष से जुड़ेगा। मिदनापुर के गोपीबल्लभपुर में पार्टी ने भूमिपतियों से जब उनके हथियार छीने तो मजूमदार ने कहा कि उनका इस्तेमाल वर्गशत्रु के सफाए के लिए नहीं, बल्कि अपने बचाव के लिए किया जाएगा। 'छह इंच छोटा करना' यानी वर्ग शत्रु का सिर उसके धड़ से अलग करना, ताकि वर्ग शत्रुओं में भय व्याप्त हो, यह माओवादियों की कार्यपद्धति बन गई।

मजूमदार ने यह भी कहा था कि माओ ने चीन की 'मुक्ति सेना' 320 राइफल से शुरु की, पर हम मात्र 60 राइफल और 200 पाइपगन से अपनी मुक्ति सेना बनाएंगे तथा वर्ग शत्रु जमींदार और उनके एजेंटों का खात्मा करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तो 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्?स-लेनिन)' यानी सीपीआइ-एमएल रखा, लेकिन वह अपने कैडर को माओ की 'रेड बुक' पढ़ने का आदेश देते थे। नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस कथित आंदोलन को देश के एक खास वर्ग का समर्थन भी मिला और इसका विस्तार भी हुआ, पर वैचारिक और व्यावहारिक स्तर पर भटकाव का शिकार होने के कारण बिखराव इसकी नियति बन गई। 'सत्ता बंदूक की नोक से निकलती है और हमारा नेता माओ'-ये ऐसे नारे थे, जिसके कारण भारत में माओवादियों का जनसमर्थन घटता गया। धीरे-धीरे माओवादी 'लेवी वसूली' पार्टी बनकर रह गए।

बिखराव के शिकार इनके एक ग्रुप 'एमसीसी' ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से भी हाथ मिलाया। 2004 में एमसीसी, सीपीआइ-एमएल और पीपुल्स वार ग्रुप ने विलय कर एक नया दल 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)' बनाया। नए बने दल के नाम से मार्क्?स एवं लेनिन का नाम गायब हो गया और परंपरागत हथियारों का स्थान आधुनिक हथियारों ने ले लिया। मार्च 2007 में पार्टी की नौवीं कांग्रेस में जो प्रस्ताव पारित हुए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि माओवादी सामाजिक और आर्थिक शोषण से मुक्ति का केवल नारा ही देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की सत्ता हड़पना है। इनका वर्ग शत्रु अब भारत का लोकतंत्र है। भारत के अर्धसैनिक बलों पर ये आधुनिक हथियारों से हमला कर रहे हैं। ये वहां-वहां हमारे जवानों की हत्या कर उनके हथियार लूट ले रहे हैं, जहां-जहां उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। मुठभेड़ के बाद मारे गए माओवादियों से आधुनिक हथियार और रॉकेट लांचर तक प्राप्त हुए हैं।

माओवादी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। इन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन की मदद की। ये जब-तब प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचते रहते हैं। इन्हें बेनकाब करने की योजनाबद्ध पहल होनी चाहिए। इन्हें नक्सली कहने के बदले माओवादी कहा जाना चाहिए। माओवादियों ने जंगल और जमीन छीने जाने का भय दिखाकर गरीब आदिवासियों में जो अपनी गहरी पैठ बनाई है, उसे दूर कर इनके असली चेहरे को सामने लाना होगा। सच तो यह है कि माओवादी यानी वसूली गैंग के नेताओं ने करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्ति भी बना ली है। गांजा-अफीम की खेती और तस्करी से इन्हें अकूत धन प्राप्त हो रहा है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर माओवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले अधिकतर जवान गांवों के गरीब किसानों और मजदूरों की ही संतानें हैं। साफ है कि माओवादियों से लड़ाई में जो खून बह रहा है वह भी गरीब का ही खून है। गरीब-गरीब को लड़ाकर माओ के वंशज भारत को न केवल सीमा पर, बल्कि देश के अंदर अघोषित युद्ध छेड़कर देश के विकास को रोकना चाहते हैं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर माओवादियों की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि नक्सली वस्तुत॰ माओवादी ही हैं। ये चीन-पाकिस्तान के दलाल भी बन गए हैं। इन्हें नेस्तनाबूद किया ही जाना चाहिए। माओवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा समय की मांग है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- गंभीर संक्रमितों को मुफ्त में रेमडेसिविर उपलब्ध कराएगी यूपी सरकार

लखनऊ । वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन में मची अफरा-तफरी के बीच में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संयम से काम ले रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मुख्यमंत्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पटरी पर लाने के बाद अब बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को सरकार मुफ्त में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएगी। जिससे वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकें।

कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री की मंगलवार को एक घोषणा बेहद मंगलकारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी अस्पतालों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रही है। यहां पर इलाज करा रहे लोगों को इंजेक्शन मुफ्त मे दिया जाएगी। हालांकि प्रदेश के निजी अस्पतालों को कंपनियों और बाजार से ही रेमडेसिविर खरीदना होगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सभी सरकारी और साथ ही राज्य के निजी अस्पतालों में सरकारी अस्पताल से रेफर होने के बाद भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को निःशुल्क रेमडेसिविर इंजेक्शन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी निजी अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और वहां पर उपचार करा रहे संक्रमित की जीवन रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, तो वहां के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को उस अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि डिमांड के अनुसार विभिन्न जिलों को पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध कराए जाएं। यदि आवश्यक हो, तो निजी अस्पतालों को भी निर्धारित दरों पर रेमडेसिविर प्रदान कराएं।

प्रदेश का चिकित्सा विभाग अभी रोज जिलों में पांच से छह हजार वॉयर रेमडेसिविर इंजेक्शन रोज उपलब्ध करा रहा है। इसका वितरण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, और उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से हो रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा दें। जिससे कि यहां पर इलाज करा रहे लोगों को इसका लाभ मिले। उन्होंने यह भी कह कि सरकारी अस्पताल में भर्ती लोगों को इंजेक्शन रेमडेसिविर मुफ्त में दिया जाए। राजधानी लखनऊ के साथ ही प्रदेश के हर जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन रेमडेसिविर को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। यदि बहुत आवश्यक हो, तो निजी अस्पतालों को भी निर्धारित दरों पर इंजेक्शन रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

कोरोना वायरस की वैक्सीन मजबूत कवच, संक्रमित को नहीं पड़ रही मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत

लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के हर नागरिक को कोरोना कैक्सीन उपल्बध कराने की सोच बेहद दूरगामी है। यह वैक्सीन सभी के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से लडने् के लिए बेहद ही मजबूत सुरक्षा कवच है। इस वैक्सीन की एक भी डोज लेने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चपेट में आने वाले लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में हैं, जहां पर उनको मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इसके साथ ही इनका रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना रोधी टीका लगवाने की बड़ी तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। माना जा रहा है कि 29 अप्रैल तक प्रदेश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 50-50 लाख डोज उपलब्ध होगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके कुछ लोग भले ही कोरोना वायरस की चपेट में हैं, लेकिन दो-चार केस को छोड़कर उनके जीवन पर संकट नहीं आ हा है।

मेडिकल एक्सपट्र्स भी मान रहे है कि कोरोना वैक्सीन के डोज लेने वालों में रिकवरी रेट बिना डोज वालों की अपेक्षा बेहतर देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने टीका लगवा रखा है, उनमें संक्रमण के गंभीर लक्षण और मेडिकल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। जिन्हें एक भी डोज लगा है, वह संक्रमित होने पर भी दूसरी लहर के संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं।

किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज के चिकित्सों का मानना है कि कोरोना वायरस टीकाकरण काफी लाभ देने वाला है। इसके टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने वालों का संक्रमण परिवारों में नहीं फैल रहा है। इसमें इस दौरान सामान्य बुखार और हल्के बदन दर्द जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों का संक्रमित होने के बाद रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। यह लोग कम से कम समय में इससे उबर भी जा रहे हैं। इनकी रिपोर्ट सप्ताह भर में रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। इन सभी के आक्सीजन का स्तर भी सामान्य ही रह रहा है। इसका लाभ डॉक्टर्स के अलावा अन्य टीका की डोज लेने वालों को भी मिला है।

संक्षिप्त खबर

कोरोना के कारण मेरठ में सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ ने बाजार बंद रखने का लिया फैसला

मेरठ । मेरठ के शास्त्रीनगर क्षेत्र के मुख्य बाजार सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के व्यापारियों ने मंगलवार को बैठक करते हुए अगले तीन दिन स्वेच्छा से संपूर्ण बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के महामंत्री महिपाल सिंह ने बताया कि व्यापारियों से विचार-विमर्श करने के बाद 28, 29 व 30 को बाजार बंद रहेगा। इसके बाद 1, 2 व 3 मई को लाकडाउन और साप्ताहिक बंदी रहेगी। बाजार 4 मई को खुलेगा।

अफवाह से बचें, बंद नहीं होंगे किराना बाजार- स्वैच्छिक बाजार बंदी करने वाले बाजारों में किराना व्यापारी शामिल नहीं होंगे। सोमवार को शहर के प्रमुख किराना बाजारों के व्यापारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है। किराना के सभी खाद्य उत्पाद दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी व खाद्य तेल आदि आवश्यक वस्तुओं में आते हैं। इसलिए सदर दाल मंडी, दाल मंडी एसोसिएशन, गंज बाजार व सदर धानेश्वर चौक बंद नहीं होंगे।

भोजपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक में दिनदहाड़े लूट, भागने के दौरान एक अपराधी गोली से घायल

आरा । बिहार के भोजपुर जिले में दिनदहाड़े बैंक लूट की घटना हुई है। आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौंटा गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में मंगलवार की दोपहर हथियार बंद अपराधियों ने धावा बोलकर लूटपाट की। इस दौरान लूटे गए रुपए का हिसाब लगाया जा रहा है। लूट की घटना के दौरान अपराधियों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इससे बचने के लिए अपराधियों ने फायरिंग भी की। बैंक लूट कर भाग रहे अपराधियों में से एक को स?थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि इस अपराधी को भी गोली लगी है। पकड़े गए अपराधी को सिर के हिस्से में गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। भोजपुर एसपी राकेश दुबे मौका ए वारदात पर पहुंच कर छानबीन कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अपराधी-पांच की संख्या में थे, जो हथियारों से लैस थे। हो-हल्ला होने.और ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने के बाद अन्य भागने में सफल रहे। जबकि, एक को ग्रामीणों ने बैंक में बंधक बना लिया। इधर, घायल अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल, आरा भेजा गया है। शुरुआती जानकारी में यह बात आ रही कि अपराधी को अपने ही साथियों द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगी है। एसपी और डीएसपी के अलावा आरा टाउन थाना, नवादा थाना, मुफस्सिल थाना, कृष्णागढ़ थाना, बड़हरा थाना की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पुलिस ने गांव से निकलने के रास्तों पर छानबीन भी शुरू की है।

बैंक के स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके अपराधी- इधर, भोजपुर एसपी राकेश दुबे ने बताया का कि शुरुआती जांच में यह बात आई है कि अपराधी चार की संख्या में थे। करीब 50 हजार रुपये ही अपराधियों को हाथ लगा है। अपराधी स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच सके, जिससे कैश बच गया। अपने साथियों द्वारा की गई फायरिंग में अपराधी को गोली लगी है। पकड़े अपराधी की मदद से बहुत जल्द गैंग को चिह्नित कर लिया जाएगा। अभी छानबीन की जा रही है।

तीन अपराधी घुसे थे बैंक के अंदर- एक ग्राहक ने बताया कि लूट के दौरान तीन अपराधी बैंक के अंदर घुसे थे। अपराधियों ने कैश काउंटर पर पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान उनके एक साथी को भी गोली लग गई। मामला बिगड़ते देखकर सभी अपराधी कैश काउंटर का पैसा लेकर भाग निकले।

पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार को दिया सुझाव, कहा- कोरोना की चेन तोड़ने को सेना की लें मदद

पटना । बिहार में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर राजनीति भी गर्म होती जा रही है। मरीजों की स्थिति देखते हुए लगातार राज्य की नीतीश सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार अगर बिहार में कोरोना के चेन को तोड़ना चाहती है तो सभी कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी है। मंगलवार को पप्पू यादव बिहटा के अमहरा स्थित एनएसएमसीएच अस्पताल एवं ईएसआइसी अस्पताल में बने कोविड वार्ड का जायजा लेने पंहुचे थे।

अस्पताल का जायजा लेने के दौरान उन्होंने कोरोना वार्ड, इलाज, भोजन, दवा आदि की सुविधा का मुआयना किया और संक्रमितों के स्वाजनों से मिलकर उनकी बातें सुनीं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो कुछ रेमडेसिविर तो कोई अपने स्वजनों को कोरोना अस्पताल में भर्ती कराने के लिये दौड़ रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम एवं हाहाकार मची है। इस वैश्विक महामारी में कुछ लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर पुण्य का काम रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को खाना दे रहा है।

पप्पू यादव ने कहा कि ऐसी विकट परिस्थित में भी कुछ लोग सुधर नहीं रहे। दवा आदि की कालाबाजारी कर अपनी जेब भरने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर बिहार में कोरोना के चेन को तोड़ना चाहती है तो सभी कोविड अस्पतालों को सेना के हवाले कर देना चाहिए। एक तरफ ऑक्सीजन और बेड के लिए मारामारी हो रही है।

कानपुर में डीएम ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराया महामारी एक्ट में केस, लॉकअप में बैठाकर छोड़ा

कानपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोरोना वायरस संक्रमण में शिथिलता बरतने वालों पर अब जिला प्रशासन बेहद गंभीर हो गया है। कानपुर में ऐसे ही एक मामले में जिलाधिकारी ने कोरोना रैपिड रेस्पॉन्स टीम के इंचार्ज पर उचित जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई की। कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी के निर्देश पर पतारा सीएचसी के इंचार्ज नीरज सचान के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज कर देर रात उनको स्वरूप नगर कोतवाली के लॉकअप में रखा गया। इसके बाद बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के लामबंद होने पर इनको छोड़ दिया गया।

कानपुर में जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने सोमवार देर शाम कोरोना वायरस संक्रमण पर बैठक के दौरान सरकारी डॉक्टर को गिरफ्तार कराया। जिलाधिकारी ने कोरोना कंट्रोल की बैठक की थी, जिसमें डॉक्टर नीरज सचान शामिल हुए थे। इस बैठक में दो दिन पहले ही कोरोना रैपिड रेस्पॉन्स टीम के इंचार्ज बनाए गए नीरज सचान पर सही से जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। जिलाधिकारी के इस कदम से कानपुर के सरकारी डॉक्टर्स में

आक्रोश फैल गया। डॉक्टर नीरज सचान, पतारा सीएचसी हॉस्पिटल के इंचार्ज थे। दो दिन पहले ही उनको कोरोना रैपिड रेस्पोंस टीम का इंचार्ज बनाया गया था।

रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कोरोना कंट्रोल की मीटिंग की थी, जिसमें डॉक्टर नीरज शामिल थे। इस मीटिंग में ही जिलाधिकारी ने आलोक तिवारी ने उन पर सही से जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। सोमवार रात में ही स्वरूप नगर थाने में डॉक्टर नीरज सचान के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज कराके स्वरूप नगर लॉकअप में डाल दिया गया। उनके खिलाफ डीएम के इस एक्शन की सूचना मिलते ही शहर के दर्जनों सरकारी डॉक्टर स्वरूप नगर थाने पहुंच कर इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता और डीसीपी भी थाने में डटे रहे लेकिन किसी अधिकारी ने यह बताना जरूरी नहीं समझा कि आखिर एक डॉक्टर जो दो दिन पहले ही टीम का इंचार्ज बना हो, उसके ऊपर पूरा कोरोना संक्रमण रोकने की जवाबदेही कैसे डाली जा सकती है।

डॉक्टर नीरज सचान का कहना है कि मैं मीटिंग में डीएम साहब को अपनी बात समझा नहीं पाया, मैंने उनसे कहा भी कि सर अभी हमको दो दिन काम करने को मिले हैं, कुछ अगर कमी रह गई है तो अगले दो-तीन दिन में सब ठीक कर लूंगा लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं हुए जबकि मेरे पास पतारा सीएचसी का भी कार्य मेरे पास पतारा सीएचसी का भी कार्यभार था। डॉक्टर नीरज सचान ने कहा कि मैंने इस दौरान जिलाधिकारी से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि यह काम सही ढंग से करना नहीं चाहते, इनके खिलाफ केस दर्ज करो। इसके बाद डीएम की मीटिंग से निकलते ही पुलिस मुझे पकड़कर थाने लाई और लॉकअप में बंद कर दिया। हालांकि देर रात इनको थाने से ही छोड़ दिया गया।

ऑक्सीजन की कमी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले- सरेआम झूठ बोल रही है भाजपा सरकार

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से देश के साथ प्रदेश में स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत से लोगों की बढ़ती परेशानी के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार माना है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। सरकार तो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में लगी है। रोग लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार मेडिकल ऑक्सीजन के साथ ही हॉस्पिटल में बेड और दवा भी मुहैया कराने में पूरी तरह से फेल है। इसके बाद भी लगातार झूठ बोला जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपनी पीड़ा पर एक ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लोग

मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं। खाली सिलेंडर लेकर यह लोग भीषण गर्मी में या तो ऑटो या फिर रिक्शा में बैठकर लम्बी दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन इनको मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से लोग भटक रहे वो बेहद ही दुःखद क्षण है। उससे भी दुःखद है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार झूठ बोल रही है। भाजपा सरकार तो अब रोज सरेआम झूठ बोल रही है। यह एक नैतिक अपराध है। भाजपा तो नैकिकता का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य का इतना अपमान पहले नहीं हुआ है।

ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में एंटीजन टेस्ट कराने आए एक व्यक्ति की मौत

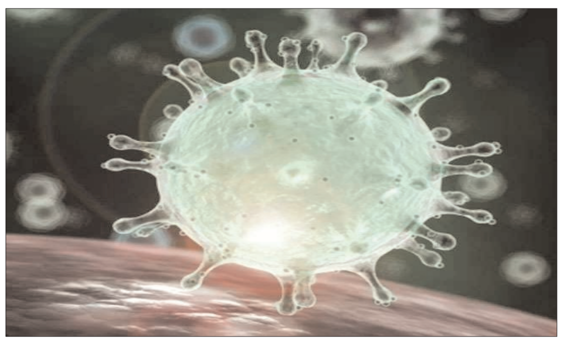

देहरादून । ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में एंटीजन टेस्ट कराने आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुरेंद्र सिंह पोखरिया (54 वर्ष) पुत्र सोनी सिंह निवासी भट्टोंवाला गुमानी वाला श्यामपुर ऋषिकेश मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे राजकीय चिकित्सालय में अपना कोविड एंटीजन जांच कराने आए थे। चिकित्सालय की लैब में जांच केंद्र में उन्होंने अपनी जांच कराई। इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। जिस पर उन्हें हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक संभवत हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक के स्वजन चिकित्सालय पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब रोज तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते रोज उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 5058 नए मामले सामने आए। बता दें ये एक दिन में कोरोना संक्रमितों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले बीते शनिवार को 5084 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं, कोरोना संक्रमित 67 मरीजों की मौत भी हुई है। अप्रैल माह में अब तक 56448 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 496 मरीजों की मौत हो चुकी है।

बुखार आने पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने खुद को किया आइसोलेट- भगवानपुर विधायक ममता राकेश की तीन दिनों से बुखार के चलते तबीयत खराब चल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ममता राकेश ने रुड़की रामनगर स्थित अपने आवास पर आइसोलेट कर लिया है। तथा स्वास्थ्य विभाग ने विधायक ममता राकेश की आरटीपीसीआर जांच भी कराई है। जिसकी रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा। वही भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि उन्होंने अपने आप को रुड़की रामनगर आवास पर आइसोलेट किया है। उनका परिवार भगवानपुर स्थित आवास पर ही रहेगा। कई दिनों से बुखार खांसी के चलते सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है।

चार नए कंटेनमेंट जोन बने, संख्या 57 हुई कोरोना संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है और इसके साथ कंटेनमेंट जोन भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। सोमवार को भी जिले में चार नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। अब जिले में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 57 हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक, राजपुर रोड पर साक्या एकेडमी के आवासीय भवन, गुनियाल गांव (पुरकुल रोड), 116/2 चंदर नगर व बंशीवाला विकासनगर क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अग्रिम आदेश तक कोई भी व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जरूरत की वस्तुओं की आपूर्ति जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएगा।

चार हवाई यात्रियों के अलावा डोईवाला में 51 पॉजिटिव- देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट में चार यात्री जांच में पॉजिटिव पाए गए। वहीं डोईवाला आसपास क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार को 51 व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डोईवाला हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर केएस भंडारी ने बताया कि संक्रमित मरीज लच्छीवाला, मिस्सरवाला, डोईवाला कोतवाली एरिया, भानियावाला, जौलीग्रांट, दूधली, बुल्लावाला, जीवनवाला, खता, लालतप्पड़, जीवनवाला, थानों रोड भानियावाला, चांदमारी, शुगर मिल कॉलोनी, प्रेमनगर बाजार के हैं। इन सभी को होम आइसोलेशन में दवा भी उपलब्ध करा दी गई है। डोईवाला हॉस्पिटल में रविवार को 171 नागरिकों की सैंपल लिए गए। वहीं 158 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। डोईवाला सीएससी केंद्र के अंतर्गत रायवाला, दुधली, भानियावाला, मियांवाला आदि क्षेत्रों में कुल मिलाकर 1030 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन भी किया गया। इसके अलावा इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मूवमेंट भी कर रही है। उधर डोईवाला तहसील के नायब तहसीलदार रूप ड्क्षसह ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले 107 यात्रियों के सैंपल लिए गए। जिसमें से चार यात्री पॉजिटिव पाए गए। जिन्हें होम आइसोलेशन किया गया है।

पटना में डेढ़ घंटे मशक्कत के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मौत, अधिकारी का जवाब चौंकाने वाला

बाढ़ (पटना)। बिहार में सरकार और जिलों का स्थानीय प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई संकट नहीं है, दूसरी तरफ लगातार अस्पताल के गेट पर पहुंचकर मरीज दम तोड़ रहे हैं। पटना जिले के बाढ़ स्थित अनुमंडल अस्पताल में सोमवार को एक बुजर्ग ने बगैर इलाज के दम तोड़ दिया। मरीज के स्वजनों का कहना है कि काफी कहने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाया। इस बाबत अस्पताल के अधिकारी ने जो कुछ कहा, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे।

खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे स्वजन- सोमवार की सुबह 10~30 बजे अथमलगोला थाना क्षेत्र के दक्षिणीचक गांव निवासी 70 वर्षीय शिवदयाल सिंह नामक कोरोना संक्रमित व्यक्ति पहुंचा। एंबुलेंस पर आए बुजुर्ग को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। परिजनों द्वारा लगाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की कगार पर था। अस्पताल पहुंचने के डेढ़ घंटे तक परिजन ऑक्सीजन मुहैया कराने की मांग करते रहे।

अस्पताल के प्रभारी डॉ. विकासचंद्र चौधरी ने कहा कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल 67 था। साथ ही पल्स भी गिरी थी। ऐसी परिस्थिति में कैसे भर्ती किया जाता। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश है कि 90 से कम ऑक्सीजन वालों को बॉन्ड भरवा कर ही भर्ती करें। ऐसी परिस्थिति में करीब डेढ़ घंटे तक मरीज ऑक्सीजन का इंतजार करता रहा। आखिरकार अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी ने परिजन होने का हवाला भी देता रहा, लेकिन एक नहीं सुनी गई। डेढ़ घंटे बाद जब लोगों ने दबाव बनाया तो उसे वार्ड में लाया गया, जहां बेड पर जाते ही बुजुर्ग की मौत हो गई।

मरीज के स्वजन चंद्र प्रकाश ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद उनकी मौत नहीं होती। इस बाबत उपाधीक्षक ने कहा कि मरीज काफी गंभीर था। कम ऑक्सीजन वाले मरीज को पटना भेजा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि समय रहते बुजुर्ग को ऑक्सीजन दे दी जाती तो क्या बिगड़ जाता बताते चलें कि अस्पताल प्रबंधन के पास ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था है। इसके बावजूद लापरवाही की खबर सामने आई है। वहीं, बाढ़ के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के स्वजनों ने भी लापरवाही की बात कहते हुए कहा कि रविवार से मेरा मरीज भर्ती है, लेकिन आज तक उसका समुचित इलाज करने को कोई तैयार नहीं है। केवल दवा ही दी जा रही है, जबकि उनकी हालत काफी नाजुक है।

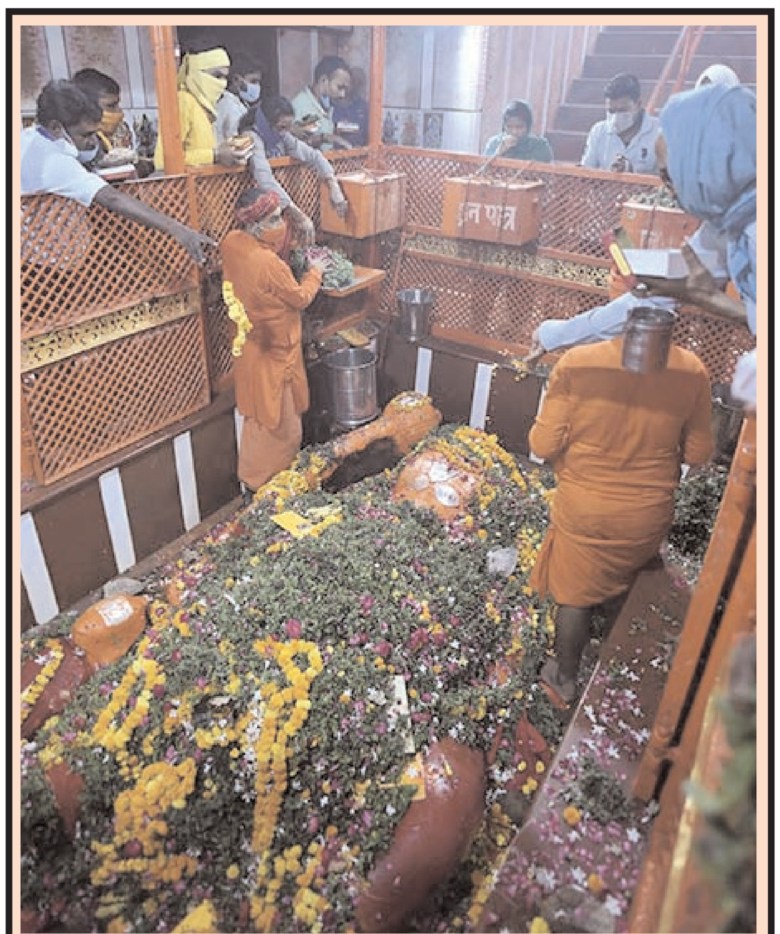

प्रयागराज में संगम के पास बाडे हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर भक्त प्रार्थना करते हुए।

पंजाब में नाइट कर्फ्यू सायं 6 बजे से, वीकेंड लॉकडाउन भी लगेगा

चंडीगढ़। पंजाब में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में वीकेंड लाकडाउन का एलान कर दिया है। यह लाकडाउन शुक्रवार शाम छह बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे तक होगा। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू को भी लाकडाउन में बदलते हुए राज्य में इसे शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। मंगलवार से अगले आदेश तक रोजाना शाम पांच बजे बाजार बंद हो जाएंगे। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

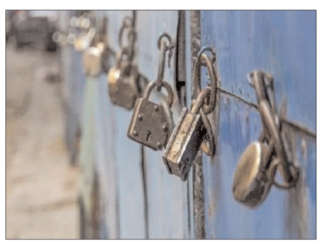

बैठक में मौजूद रहे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रधान सुनील जाखड़ ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट में चर्चा करने बाद यह आदेश दिए गए हैं। उन्होंने पूर्ण तौर पर लाकडाउन लगाने से इन्कार करते हुए कहा कि इससे जहां आर्थिक गतिविधियां रुकती ही हैं वहीं रोज कमा कर खाने वालों को भी मुश्किल आती है।

बैठक में आक्सीजन की बढ़ रही मांग और आपूर्ति को लेकर भी चर्चा की गई। यह मामला केंद्र व पंजाब सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है। पंजाब सरकार 300 टन आक्सीजन की मांग कर रहा है तो केंद्र सरकार 105 टन आक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के पास आक्सीजन का पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन उसे लेने के लिए केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही।मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पास उठा रहे हैं। अगर यह आक्सीजन हमें मिल जाती है तो इसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जाखड़ ने कहा कि अगर आक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत हुई तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। जाखड़ ने कहा कि अमृतसर में एक एक्सपोर्ट कंपनी के पास रेमिडिसिवर के 50 हजार इंजेक्शन पड़े हैं और वह मुफ्त में देने को तैयार है लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए भी मना कर दिया है। जबकि राजस्थान ने 20 हजार इंजेक्शन पंजाब को भेज दिए हैं। राज्य में इस समय वैक्सीन की भी कमी है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद हुए कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने नई एसआइटी का गठन कर दिया है। बैठक में कानूनी माहिरों ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआइटी को रद करने का फैसला लेते समय जो टिप्पणियां की हैं वह करने का हाई कोर्ट को अधिकार नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए।

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में कोरोनोवायरस की दूसरी लहर महामारी से 15 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासियों को उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया।

परिवार के सदस्य और माता-पिता रांची के सेरेंगडीह गाँव में अपने घर के बाहर बड़े बेटे निर्मल शांडिल्य की तस्वीर दिखाते हुए, उत्तराखंड के चमोली जिले के पास नीती घाटी के सुमना क्षेत्र में एक ग्लेशियर के टूटने से निर्मल शांडिल्य की मौत हो गई।

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल कोविद -19 वार्ड में कोरोनावायरस मरीज।

एक नजर

मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज कराई गई भ्रष्टाचार की शिकायत

मुंबई । महाराष्ट्र पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक से शिकायत की है। साथ ही, सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत की प्रति राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल को भी भेजी गई है। यह जानकारी सोमवार को एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि अकोला पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात इंस्पेक्टर बीआर घडगे ने 20 अप्रैल को डीजीपी को पत्र लिखकर शिकायत की है। पिछले महीने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से तबादला होने के बाद परमबीर के खिलाफ भ्रष्टाचार की यह दूसरी शिकायत है। वर्तमान में परमबीर महाराष्ट्र होम गार्ड के महानिदेशक हैं। उन्हें अंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में सरकार की किरकिरी होने के बाद हटाया गया था।

इससे पहले मुंबई के पुलिस अधिकारी अनूप डांगे ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। डीजीपी को भेजे गए 14 पेज के शिकायती पत्र में इंस्पेक्टर घडगे ने दावा किया है कि वर्ष 2015-18 के दौरान ठाणे पुलिस आयुक्त के पद पर रहते हुए परमबीर कई स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। पत्र में वरिष्ठ आइपीएस परमबीर के खिलाफ जमीनों के सौदे, सरकारी आवास व सुरक्षा कर्मियों के दुरुपयोग समेत कई आरोप लगाए गए हैं। घडगे का कहना है कि जब परमबीर थाणे के पुलिस आयुक्त थे तब वह बाजार पेठ पुलिस थाने में तैनात थे। घडगे ने अपने पास परमबीर सारा कच्चा चिट्ठा होने का दावा किया है। इस मामले में टिप्पणी के लिए परमबीर उपलब्ध नहीं हो सके। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर एक पुलिस निरीक्षक द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि आदेश के मुताबिक सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे को सौंपी गई है। परमबीर सिंह पर पुलिस निरीक्षक अनूप डांगे ने आरोप लगाए थे। डांगे को पिछले वर्ष निलंबित कर दिया गया था, लेकिन हाल में बहाल कर दिया गया। डांगे के दावे के मुताबिक उनके निलंबन को रद करने के बदले सिंह ने उनसे दो करोड़ रुपये की मांग की थी। सिंह की इस मांग के बारे में सूचित करते हुए निरीक्षक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पत्र लिखा था। हालांकि सिंह ने डांगे के आरोपों से साफ इन्कार किया है। सूत्रों ने बताया कि शिकायत के आधार पर गृह विभाग ने सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

कोरोना संक्रमण को निमंत्रण दे रही है टीकाकरण केन्द्रों पर उमड़ रही भीड़- प्रशासन लाचार

भुवनेश्वर । कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राजधानी भुवनेश्वर के तमाम टीकाकरण केन्द्रों में कोरोना टीका लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन टीकाकरण केन्द्रों में लोग ना ही शारिरिक दुराव का अनुपालन कर रहे हैं और ना सही ढंग से मास्क पहन रहे हैं। यदि यही आलम रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली एवं मुम्बई की तरह ओडिशा में भी कोरोना की स्थिति गम्भीर हो जाएगी। ऐसे में बुद्धिजीवियों ने सरकार एवं प्रशासन से इस पर ध्यान देने के लिए मांग किया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दुसरी लहर जब से आयी है तब से लोगों में कोरोना टीका लगवाने को लेकर अधिक बेचैनी देखी जा ही है। इस बेचैनी का आलम यह है कि भारी संख्या में सुबह सुबह लोग आधारकार्ड एवं जरूरी कागजात लेकर अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर एवं अन्दर जमावड़ा लगाने वाले लोग शायद यह भूल गए हैं कि जिस महामारी से बचने के लिए वह यहां पर एकत्र हुए हैं, वह जाने अनजाने में इसी महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं।

अत?याधिक संख्या में लोग एकत्र ना होने पाए सरकार इसके लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रही है, प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्र में लाकडाउन एवं शट डाउन किया जा रहा है। शादी समारोह से लेकर अंत्येष्टि तक में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। बावजूद इसके कोरोना टीका लेने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोगों का अच्छा खासा हुजूम हर दिन साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक व्यक्ति को टीका लगवाना है तो उसके साथ और दो लोग अस्पताल परिसर भीड़ जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, मगर प्रशासन एक दो चक्कर लगाने बाद अपने दायित्व का इतिश्री कर ले रहा है। इन केन्द्रों में आने वाले लोगों में से कौन संक्रमित है, कौन नहीं, यह किसी को नहीं पता है और लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार एवं प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, विविध सामग्री की बड़ी खेप जब्त

कोलकाता । दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक बड़ी तस्करी की कोशिशों को नाकाम करते हुए तंबाकू, सौंदर्य सामग्री, चप्पल तथा कई प्रकार के विविध सामग्री की बड़ी खेप को जब्त किया। बीएसएफ की ओर से एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 6.32 लाख रुपये से ज्यादा हैं।

इन सभी वस्तुओं को उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) पेट्रापोल से होकर तस्करी के माध्यम से अवैध तरीके से पड़ोसी देश ले जाया जा रहा था। बयान के मुताबिक, 25 अप्रैल को प्राप्त खुफिया सूचना पर कार्य करते हुये आईसीपी पेट्रापोल, 179 वाहिनी, सेक्टर कोलकाता के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पार्किंग एरिया के इलाके में एक विशेष गश्त ड्यूटी पर थे। इस दौरान गश्त पार्टी को पार्किंग एरिया मे 12 बड़े बैग लावारिस हालत मे मिले। जवानों ने जब इन सभी बैगों की जांच पड़ताल की तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विविध सामग्री भरी हुई थी। सर्च पार्टी ने सामग्री को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। जब्त की गई सभी वस्तुओं को कस्टम कार्यालय पेट्रापोल को अग्रिम कानूनी कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया है।

बीएसएफ कमांडेंट ने जवानों की प्रशंसा की- इधर, 179 वाहिनी बीएसएफ के कमांडेंट अरुण कुमार ने अपने जवानों की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को नाकाम करते हुए दवाइयां, सौंदर्य सामग्री व अन्य प्रकार की विविध सामग्री की बड़ी खेप जब्त को किया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल ड्यूटी पर तैनात उनके जवानों द्वारा प्रदर्शित सतर्कता के कारण ही संभव हो सका है।

ऑक्सीजन की कमी और दवा को लेकर राजस्थान सरकार का केंद्र पर हमला

जयपुर । बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी और अन्य जीवन रक्षक दवाईयों की कमी को लेकर राजस्थान सरकार लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री मोदी सरकार पर राजस्थान के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने दो दिन पहले कहा कि ज्यादा मरीज होने के बावजूद केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों को राजस्थान से ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है।

केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों व अधिकारियों का एक समूह गठित किया है जो दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों के समक्ष ऑक्सीजन एवं दवाईयों के अधिक आवंटन को लेकर पक्ष रखेगा। इसी बीच खुद

राजस्थान सरकार की लापरवाही सामने आई है। केंद्र सरकार ने अलवर में 600 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पिछले साल स्वीकृति जारी कर थी। पीएम केयर से इसके लिए बजट का आवंटन भी हो गया था। लेकिन चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण यह प्लांट अब तक नहीं लग सका। अलवर जिला अस्पताल में लगने वाले इस प्लांट के लिए मशीनें भी आ गई,लेकिन इन्हें लगाया नहीं गया। अब जब बढ़ते संक्रमितों के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी तो जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सरकार से प्लांट शुरू करने का आग्रह किया है।

पहाड़िया ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर सुधीर शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि ऑक्सीजन की खपत लगातार बढ़ रही है,यहां डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्लांट शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसकी स्वीकृति दी। इस साल मार्च में मशीनें भी आ गई, लेकिन प्लांट को शुरू नहीं किया जा सका। इसके साथ ही टोंक, करौली, भरतपुर, दौसा और धौलपुर जिलों में रिफिल प्लांट नहीं होने के कारण जयपुर से ऑक्सीजन भेजी जा रही है।

ऑक्सीजन पर राजनीति, भाजपा ने साधा निशाना- ऑक्सीजन,अन्य आवश्यक दवाईयों की आपूर्ति का कोटा बढ़ाने और परिवहन सेवा देने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार लगातार केंद्र पर हमला बोल रही है। अब संसदीय कार्यमंत्री शांतिधारीवाल, उर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा व जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत को दिल्ली भेजा गया है। ये सभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्द्धन, रेलमंत्री पीयूष गोयल, परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मण्डाविया से मिलकर प्रदेश में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। उधर भाजपा के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्र सरकार से वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद गहलोत सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को लिक्विड ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हिस्सा आवंटित किया है। जामनगर से वायुसेना द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन जोधपुर पहुंचाई जा रही है।

ओडिशा में बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप, पुरी जिले के सभी धर्मानुष्ठान बंद

पुरी । कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुरी जिले के सभी धर्मानुष्ठान को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने 15 मई तक मंदिर, चर्च, मस्जिद आदि तमाम धर्मानुष्ठान को बंद रखने का निर्णय लिया है। इन धर्मानुष्ठानों में केवल रीति नीति का पालन किया जाएगा, भक्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 15 मई के बाद उस समय की स्थिति को देखकर पुन- आगे का निर्णय लिए जाने की जानकारी पुरी के उप जिलाधीश भव तारण साहू ने दी है। इससे पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से पुरी जगन्नाथ मंदिर को 15 मई तक बंद कर दिया गया है।

गौरतलब है कि कोरोना प्रकोप को देखते हुए पुरी जगन्नाथ मंदिर को 15 मई तक बंद करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इस समय के दौरान जगन्नाथ मंदिर में किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं है। महाप्रभु की रीति नीति याथवात चल रही है।

कोरोना की दूसरी लहर में जगन्नाथ मंदिर के कई सेवक, कर्मचारी संक्रमित हुए हैं।आगे की स्थिति अधिक गम्भीर हो सकती है। ऐसे में श्रीजीउ की नीति प्रभावित ना होने पाए, इसके लिए भक्तों को जगन्नाथ मंदिर को बंद करने का निर्णय जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की तरफ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 15 तारीख से 21 दिवसीय महाप्रभु की चंदनयात्रा है। महाप्रभु की चलंति प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर चंदन पुष्करिणी में जलक्रीड़ा करती हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण महाप्रभु की चंदन यात्रा श्रीमंदिर के अन्दर ही गई थी। ऐसे में इस साल महाप्रभु की चंदन यात्रा जगन्नाथ मंदिर के बाहर होगी या मंदिर के अन्दर ही सम्पन्न होगी उस संदर्भ में आगामी 6 तारीख को होने वाली बैठक में निर्णय लिए जाने की जानकारी मंदिर प्रशासन की तरफ से दी गई है।

गुजरात में कोरोना के 14340 नए मामले, गरबा करने पर 12 लोगों पर केस

अहमदाबाद । गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14340 नए मामले सामने आए, 158 मौतें हुईं और 7,727 रिकवर हुए। कुल मामले 5,10,373 हैं। सक्रिय मामले 1,21,461 हैं। वहीं, आणंद में गरबा खेलने पर पुलिस ने 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। इधर, गुजरात सरकार ने 18 से 45 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए टीका के डेढ़ करोड़ डोज की व्यवस्था की है। गुजरात में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एक मई से राज्य सरकार की ओर से निशुल्क टीका लगाया जाएगा। सरकार ने पूना की सिरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड टीका के एक करोड़ डोज तथा हैदराबाद के भारत बायोटेक को 50 लाख टीका के डोज का आर्डर कर दिया है।

गुजरात में मुफ्त लगेगा कोरोना का टीका- राज्य सरकार की ओर से कोरोना का टीका पूरी तरह निशुल्क लगाया जाएगा। टीका लगाने के लिए राज्य के 6000 हेल्थ सेंटर सिविक सेंटर अन्य सरकारी कार्यालयों पर व्यवस्था की गई है।

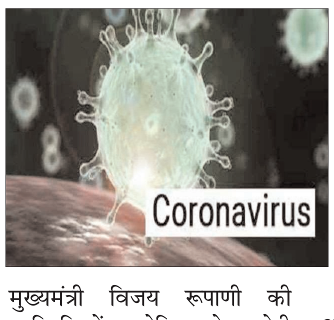

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में राज्य में एक मई से वृहद टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब तक एक करोड़ 13 लाख टीका लगाए जा चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक में गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा मुख्य सचिव अनिल मुखिया मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार दास सचिव अश्विनी कुमार स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव डॉ जयंती रवि सचिव संजीव कुमार हरीश शुक्ला धनंजय द्विवेदी तथा स्वास्थ्य आयुक्त जय प्रकाश शिवहरे आदि उपस्थित थे।

गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष परेश धनानी ने अमरेली जिला कांग्रेस व परिवर्तन ट्रस्ट की मदद से अपने विधानसभा क्षेत्र अमरेली में प्राण वायु (आक्सीजन) सेवाकेंद्र सिलेंडर की सेवा शुरू की है। धनाणी ने कोरोना की पहली लहर के दौरान भी निशुल्क भोजन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 18 लाख लोगों को भोजन पहुंचाया गया था। राज्य में को ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए नेता विपक्ष ने अब लोगों को निशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके लिए सिलेंडर लेने वाले को पेड़ लगाने का शपथ पत्र भरकर देना होगा तथा उसकी बड़ा होने तक देखने करने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिला कांग्रेस कार्यालय अमरेली के शरद धनानी मनसुख भंडारी जनक भाई पंड्या संदीप पंड्या व जगदीश मेवाड़ा तथा धर्मेंद्र पानसूरिया आदि आक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेंगे।

गरबा करने वाले 12 लोगों पर पुलिस ने किया केस – गुजरात में गरबा घर-घर की पसंद है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान आणंद के कुछ महिला-पुरुषों को गरबा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आणंद के उमरेठ थाना क्षेत्र के एक गांव में घर पर धार्मिक आयोजन के दौरान सार्वजनिक स्थल पर गाना बजाकर गरबा करने को लेकर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस इनसे मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना भी वसूलेगी। उमरेठ थाना इलाके के रतनपुर गांव निवासी रमेश शिवा सोलंकी के भगती फलिया स्थित घर पर गत 24 अप्रैल को एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद परिवार, पड़ोसी व संबंधियों ने गाना बजाकर गरबा किया तथा इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो उमरेठ पुलिस के हाथ लगते ही उसने पहले इसकी सच्चाई पता की तथा घटना सही पाए जाने पर रमेश सोलंकी, महेश सोलंकी सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत के बालाजी को नारियल चढ़ाने के बयान पर होने लगी सियासत, वैभव गहलोत ने बताया बेतुका

जोधपुर । जोधपुर के सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को जोधपुर के प्रमुख कोविड-समर्पित अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान मरीजों के परिजन से मिलने के साथ चिकित?सा पर विश्वास के साथ बालाजी महाराज पर भरोसा रख नारियल चढ़ाने की बात कहने पर इंटरनेट मीडिया पर ट्रोल हो गये।

इसको लेकर अब सियासत भी होने लगी है। शेखावत के इस बयान पर मुख्यमंत्री के पुत्र और लोकसभा चुनावों में शेखावत के सामने कांग्रेस के प्रत?याशी रहे वर्तमान में आरसीए चेयर मेन वैभव गहलोत ने इसे बेतुका करार देते हुए गहरी निंदा की है। इधर शेखावत ने भी इस पूरे प्रसंग को अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर शेयर कर परिजनों की परिस्थिति को देखते हुए मानवीय पहलू से हिम्मत बंधाने वाला प्रयास बताया है।

आरसीए के अध्यक्ष एवं जोधपुर से लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत ने गजेन्द्र सिंह के नारियल चढ़ाओ, ठीक हो जाओगे जैसा उत?तर देने के बयान की गहरी निंदा की है। वैभव गहलोत ने कहा की जोधपुर की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनको लोकसभा में भेजा पर आज संकट के समय लोगों की मदद करने की जाए ऐसे बेतुके बयान देकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे है।

वैभव ने कहा की भारत सरकार में केबिनेट मंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठे होने के बावजूद शेखावत को चाहिए था की कोविड से लड़ाई लड़ रहे प्रदेश की केंद्र से आर्थिक मदद करवाने में सहयोग करें, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था में सहयोग करते तथा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को फ्री वैक?सीन के लिए दिल्ली में आवाज उठाने के साथ ही जोधपुर के लिए विशेष व्यवस्था करवाने के बजाए इस मुश्किल दौर में मदद मांगने पर लोगों का मजाक उड़ा रहे है। वैभव गहलोत ने कहा जोधपुर ही जनता अच्छे से भाजपा के इन नेताओं की कथनी और करनी को देख रही है आने वाले समय में इनको करारा जवाब देगी। इस मुश्किल घड़ी में राज्य सरकार सम्पूर्ण प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है।

संपूर्ण प्रकरण पर केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष व विरोधियों से सवाल पूछते हुए कहा है अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन को ढाढ़स बंधाना किस मानसिकता से गलत है, यह स्पष्ट किया जाए।

बंगाल में कोरोना के फिर रिकॉर्ड 15,992 नए मामले सामने आए, 68 की मौत

कोलकाता । बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहा है। सोमवार को राज्य में एक बार फिर पिछला सभी रिकॉर्ड टूटते हुए एक दिन में करीब 16,000 नए मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 15,992 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,59,942 हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।बुलेटिन के अनुसार, संक्रमण के चलते 68 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा ग्यारह हजार को पार कर कुल संख्या 11,009 हो गई है। बता दें कि राज्य में एक दिन पहले भी रिकॉर्ड 15,889 नए मामले आए थे एवं 57 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई थी। राज्य में बीते 24 घंटे में 9,775 लोग संक्रमण से उबरे भी हैं। राज्य में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 6,53,984 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन रोगियों (एक्टिव केस) की संख्या बढ़कर 94,949 हो गई है। वहीं, राज्य में 94 हजार से ज्यादा एक्टिव केस होने के चलते रिकवरी रेट घटकर 86.06 हो गई है, जो एक दिन पहले 88.59 थी। वहीं, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 48,562 नमूनों की जांच की गई है। इससे एक दिन पहले 55,600 नमूनों की जांच की गई थी जिसमें 15,889 नए मामले सामने आए थे।

उसकी तुलना में पिछले 24 घंटे में करीब 48,000 नमूनों की जांच में ही रविवार की तुलना में ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में किस रफ्तार से संक्रमण लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इधर, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान जो नए मामले आए हैं उनमें कोलकाता में फिर सबसे अधिक 3,868 जबकि उत्तर 24 परगना में 3,425 मामले हैं।

वहीं, बीरभूम जिले में 704, मालदा में 644 एवं मुर्शिदाबाद जिले में 502 नए मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि कोलकाता की सात सीटों समेत बीरभूम, मालदा व मुर्शिदाबाद जिले में आठवें चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है।उससे पहले जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है यह चिंताजनक है। कोलकाता में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से सर्वाधिक 26 लोगों की जबकि उत्तर 24 परगना जिले में 11 लोगों की मौत हुई है।

बंगाल में सामान्य दिनों में राजनीतिक हिंसा और चुनावी मौसम में हिंसा के अलग-अलग मायने

कोलकाता । बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। वर्ष 1960 से 70 के बीच राज्य में जो हिंसा शुरू हुई वह आज तक बदस्तूर जारी है। बंगाल के चुनावों में हमेशा से हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी वाममोर्चा पर हिंसा का आरोप लगाती थीं। उसी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और सत्ता के शिखर पर पहुंचीं। अब तृणमूल पर भी उसी हिंसा का आरोप भाजपा की ओर से लग रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक आरोप लगा रहे हैं कि पिछले तीन वर्षों में उनकी पार्टी के 135 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। हालांकि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी आरोपों को खारिज कर भाजपा को ही दंगाई पार्टी बताती हैं। पर, सात चरणों के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उसके संकेत बड़े हैं। पिछले दो दशकों के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हिंसा से सूबे की सियासी तस्वीर बिगड़ती रही है।

चुनाव आयोग मतदान के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने के दावे करता रहा है, लेकिन चरण दर चरण हिंसा होती रही। मतदान का एक भी चरण ऐसा नहीं बीता जिसमें खून नहीं बहा हो। यहां तक कि प्रत्याशियों को भी नहीं बख्शा गया। सोमवार को सातवें चरण में 34 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने हर संभव उपाय किए, लेकिन हालत वही ढाक के तीन पात।

बंगाल में हिंसा के इतिहास को देखते हुए ही आयोग ने शांतिपूर्ण, निर्बाध मतदान के लिए हर चरण में एक लाख से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस र्किमयों को तैनात किया। परंतु हिंसा रोकने में कामयाबी नहीं मिली। वैसे मतदाताओं को भयमुक्त माहौल देने की पूरी कोशिश अब भी जारी है। देखने वाली बात है कि अंतिम चरण में स्थिति क्या होती है?

बंगाल की चुनावी राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषकों की मानें तो हिंसा के पीछे महत्वपूर्ण सियासी संकेत होते हैं। उनके मुताबिक राज्य में हिंसा का राजनीतिक बदलाव से गहरा संबंध रहा है। हिंसा राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का बड़ा कारक रही है। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव, 2008 के पंचायत चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव, 2010 के शहरी निकाय और 2011 के विधानसभा चुनाव समेत 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव इसके उदाहरण हैं। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में भले ही वाममोर्चा को जीत मिली थी, लेकिन उसकी सियासी जमीन उसी समय खिसकने लगी जिसका परिणाम 2008 और 2009 के पंचायत व लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। इसी तरह से 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई और नतीजा सर्वविदित है।देखा जाए तो वर्ष 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका है जब तृणमूल के सामने एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा के बाद भी भगवा पार्टी मुख्य विपक्षी बन गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 फीसद से अधिक वोट प्राप्त कर 42 में से 18 सीटें जीत गई। हिंसा की एक बड़ी वजह भाजपा का यह उभार भी है। बंगाल में करीब 30 फीसद मुसलमान और लगभग 29 फीसद अनुसूचित जाति व जनजाति के मतदाता हैं। कभी वामपंथियों का वोटबैंक माने जाने वाले मुसलमान व एससी-एसटी 2011 से ही तृणमूल की ओर चले गए। वहीं पिछले पंचायत व लोकसभा चुनाव में एससी एसटी वोट भाजपा की ओर मुड़ गया। वहीं तृणमूल और वामदलों के जनाधार में आ रहे बदलाव ने भाजपा को दो मोर्चों 'पंथ और वर्ग' को एकजुट करने का मौका दे दिया। साथ ही भाजपा को शहरी बंगाल के मध्यम वर्ग के हिंदुओं और ग्रामीण बंगाल में एससी-एसटी समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाने का अवसर प्रदान कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज भगवा ब्रिगेड सत्ता के रेस में शामिल है।

ऐसे में चुनावी हिंसा अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हर हाल में चुनाव जीतने की जो प्रवृत्ति है वह चुनाव के दौरान खून-खराबे को और हवा दे रही है।

टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुकी हैं फातिमा सना शेख,

बहुत मुश्किल होता है

फिल्म 'दंगल' फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख हाल ही में रिलीज हुई 'अजीब दास्तांस' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच वो अपने रिलेशनशिप को लेकर किए खुलासों को लेकर भी चर्चा बटोर रही हैं। फातिमा वैसे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बात की है। फातिमा ने खुलासा किया है कि वह एक खराब रिलेशनशिप में रही हैं। उन्होंने कहा, मैं भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। यह बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन, जब आप किसी के संग रिश्ते में होते हैं तब यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खासकर जब आप फाइनेंशियली रूप से अपने हसबैंड पर डिपेंड होते हैं। वहीं फातिमा ने अपनी पिछली रिलीज फिल्म 'लूडो' के बारे में बात करते हुए कहा कि 'लूडो' में निभाए पिंकी के कैरेक्टर से वह पूरी तरह से अलग हैं। वह कहती हैं कि इस फिल्म में निभाये गए किरदार पिंकी की तरह मैं कदाचित भी नहीं हूं। पतिव्रता लड़की। मेरे साथ कोई ऐसी चीज करे तो दो थप्पड़ मार दूं। बता दें कि फातिमा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया है। इसके बाद आमिर खान की फिल्म दंगल से उन्हें पहचान मिली। दंगल के बाद वह ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां, लूडो, सूरज पे मंगल भारी और आकाश वाणी में नजर आ चुकी हैं। फातिमा ने कुछ दिनों पहले कास्टिंग काउच को लेकर बड़ा खुलासा किया था। फातिमा ने कहा था कि कुछ डायरेक्टर्स की डिमांड नहीं मानने की वजह से उनसे कई फिल्में छीन ली गई थीं। उन्होंने कहा था, मुझे कहा गया था कि तुम्हें तब ही काम देंगे जब तुम हमारी डिमांड पूरी करोगी। मैंने वैसा करने से मना कर दिया था और इसके बाद मुझे काम नहीं दिया गया।

निक्की तंबोली डोनेट करेंगी प्लाज्मा

बिग बॉस 14 की सेकंड रनरअप निक्की तंबोली कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करेंगी। निक्की तंबोली सरकारी अस्पताल में प्लाज्मा डोनेट करेंगी। यह खुलासा उनके भाई ने किया है। वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निक्की तंबोली ने भी हाल ही में कोरोना से जंग जीती है। 19 मार्च को निक्की ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन कर रही थीं। निक्की ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि वे सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा का दान करेंगी। उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी कोरोनावायरस को लेकर सजग रहने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निक्की ने अपने भाई की भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। निक्की ने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मैं कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेट करूंगी और उन लोगों से भी प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करती हूं जो कोरोना से जंग जीत चुकी है।

एंथनी हॉपकिन्स को 'द फादर' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर

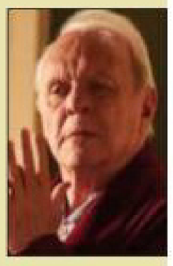

जाने-माने हॉलीवुड कलाकार एंथनी हॉपकिन्स ने 93वें अकादमी पुरस्कार में फिल्म 'द फादर' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अभिनेता के लिए यह पुरस्कार जीतना काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि अधिकतर लोग दिवंगत कलाकार चैडविक बोसमैन को उनकी फिल्म 'मा रेनीज ब्लैक बॉटम' में भूमिका के लिए पुरस्कार का दावेदार मान रहे थे। फिल्म 'साउंड ऑफ मेटल' में अपने प्रदर्शन के लिए अभिनेता रिज अहमद भी पुरस्कार के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। कोलोन कैंसर से 4 साल तक जूझने के बाद 2020 में बोसमैन का निधन हो गया। इस वर्ग में नामांकित अन्य कलाकारों में गैरी ओल्डमैन और स्टीवन यून का नाम भी शामिल है। अभिनेता ने दूसरी बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इससे पहले 1991 में वे 'द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स' के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं। फ्लोरिन जेलर द्वारा निर्देशित 'द फादर' उनके अपने प्रशंसित नाटक 'ले पेरे' (द फादर) पर आधारित है। जेलर ने फिल्म का सह-लेखन भी किया है।

रकुल प्रीत सिंह निभाएंगी अपने करियर का सबसे बोल्ड किरदार

बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह कई शानदार फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वहीं रकुल अपने करियर का सबसे अलग किरदार भी निभाने वाली हैं जो आज तक किसी एक्ट्रेस ने नहीं किया। रॉनी स्क्रूवाला रकुल प्रीत सिंह के साथ वुमन सेंट्रिक फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह जो किरदार निभाने वाली हैं जो काफी चौकाने वाला है। खबर है कि इस फिल्म में रकुल एक कॉन्डम टेस्ट करने वाली महिला के रोल में नजर आने वाली हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर किसी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सोशल कॉमेडी फिल्म में रकुल प्रीत सिंह को पहली बार देखना काफी अलग सा अनुभव होने वाला है। फैंस इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं लेकिन अभी फिल्म के टाइटल को लेकर ऐलान नहीं हुआ है। रकुल प्रीत सिंह की इस खबर के बाद इस फिल्म की कहानी को लेकर भी चर्चा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री उन लोगों को कॉन्डम के बारे में जानकारी देती नजर आने वाली हैं जो कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस समय इस तरह का कई फिल्में बन रहीं हैं जो कि सोशल मैसेज देती हुईं नजर आ रहीं हैं। रकुल जल्द ही अर्जुन कपूर के साथ फिल्म सरदार का ग्रैंडसन में नजर आने वाली हैं। 'सरदार का ग्रैंडसन' एक नेटफ्लिक्स ओरिजनल फिल्म है, जिसे ओटीटी पर 18 मई को रिलीज किया जाएगा।

बॉलीवुड में कदम रखेंगे गुलशन ग्रोवर के बेटे संजय,

ओशो की पहली सेक्रेटरी लक्ष्मी पर बनाने जा रहे सीरीज

बॉलीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर ने जबरदस्त अभिनय और अंदाज से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। गुलशन ग्रोवर को विलेन के किरदार में काफी पसंद किया जाता है। अब खबर आ रही है कि गुलशन के बेटे संजय ग्रोवर भी बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं। खबरों की मानें तो संजय अध्यात्म गुरु ओशो की पहली सेक्रेटरी लक्ष्मी पर एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। इस सीरीज को संजय खुद प्रोड्यूसर करेंगे। एक इंटरव्यू में गुलशन ने कैलिफोर्निया से लौटे अपने बेटे के करियर को लेकर अहम जानकारी दी है। गुलशन ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। मेरा बेटा संजय जल्द ही एक बड़ी वेब सीरीज को प्रोड्यूस करेगा। गुलशन ने आगे बताया कि संजय राहुल मित्रा के साथ मिलकर मां लक्ष्मी पर आधारित इस वेब सीरीज का निर्माण करेंगे। बता दें कि राहुल ने इससे पहले कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। राहुल 'साहेब बीवी गैंगस्टर' फेंचाइजी की फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। गुलशन ने कहा कि संजय MGM स्टूडियोज कैलिफोर्निया में विएटिविटी, फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बेटे को उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके भारत बुलाया है। गुलशन की मानें तो संजय सिनेमा के बारे में काफी कुछ अध्ययन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि संजय दुनियाभर के सिनेमाजगत पर अपनी नजर रखते हैं। उन्होंने आगे अपनी इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि वह भविष्य में अपने बेटे को बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए देखना चाहते हैं। इस वेब सीरीज को बनाने का आइडिया राहुल ने गुलशन के सामने रखी थी। इसके बाद राहुल और संजय दोनों को सीरीज बनाने का आइडिया पंसद आया। खबरों के मुताबिक, ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन के अतुल आनंद ने राशिद मैक्सवेल की किताब 'द ओनली लाइफः ओशो, लक्ष्मी एंड ए जर्नी ऑफ द हार्ट' भेजी थी। इसके बाद राहुल ने इस किताब के राइटस खरीद लिए थे। खबरों की मानें तो संजय अपने पिता की तरह बड़े अभिनेता बनना नहीं चाहते हैं। ओशो की पूर्व सहयोगी मां आनंद शीला पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'सर्चिंग फॉर शीला' लंबे समय से चर्चा में है। डॉक्यूमेंट्री का सह-निर्माण कर रहे करण जौहर ने हाल में सोशल मीडिया पर इसका ट्रेलर शेयर किया था। 'सर्चिंग फॉल शीला' 22 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है। इसमें मां आनंद शीला के जीवन से जुड़े कई रहस्यों को उजागर किया गया है।

अकादमी अवॉर्ड के 'स्मृति' वर्ग में इरफान खान और भानु अथैया को किया गया याद

भारतीय अभिनेता इरफान खान और भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के 'स्मृति' खंड में सम्मानित किया गया। हर साल की तरह अकादमी पुरस्कार ने 3 मिनट के 'इन मेमोरियम' मोंटाज (तस्वीरों का वीडियो कोलॉज) में फिल्मी जगत के उन दिग्गज सितारों को याद किया जिनका पिछले 1 साल में निधन हुआ है। खान और अथैया के अलावा चैडविक बोसमेन, सीन कॉनरी, क्रिस्टोफर प्लमर, ओलिविया डे हैवीलैंड, किर्क डोगलस, जॉर्ज सेगल, निर्देशक किम की डक, मैक्स वोन साइदो और अन्य को भी तस्वीरों के जरिए इस खंड में याद किया गया। भारत के दिग्गज कलाकारों में से एक खान (54) का पिछले साल 28 अप्रैल को कैंसर की दुर्लभ बीमारी से लड़ते हुए मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। अथैया को मस्तिष्क का कैंसर था और उनका 91 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद पिछले साल 15 अक्टूबर को अपने घर में निधन हो गया था। उन्होंने 1983 में रिचर्ड एटनबरो की महात्मा गांधी पर बनी बायोपिक 'गांधी' के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर जीता था। इस फिल्म को 8 ऑस्कर मिले थे। फिल्म में बेन किंग्सले ने महात्मा की भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला था। अथैया ने 2012 में अपना ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज को लौटा दिया था ताकि पुरस्कार सुरक्षित रखा जा सके।

आईपीएल खेल रहे इस खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट बोर्ड से की गुजारिश, स्वदेश लौटने की करें व्यवस्था

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में खेल रहे कई विदेशी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। इस बीच, मुंबई इंडियन्स के बल्लेबाज क्रिस लिन ने क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों के स्वदेश लौटने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उनकी फ्रेंचाइजी अगले सप्ताह टीम के सभी सदस्यों पर टीका लगवाएगी।

आस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ी एंड्रयू टाइ, केन रिचर्डसन और एडम जंपा भारत में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण आईपीएल से हट गए हैं। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने सोमवार को आईपीएल में खेल रहे अपने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और यात्रा योजनाओं के बारे में जानकारी ली थी। लिन ने कहा, ''मैंने वापस संदेश भेजा है कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया प्रत्येक आईपीएल अनुबंध का 10 प्रतिशत हिस्सा लेता है और क्या ऐसी कोई संभावना है कि आईपीएल समाप्त होने पर इस वर्ष यह धनराशि विशेष विमान पर खर्च की जाए।''

लिन ने कहा, ''मैं जानता हूं कि लोगों की स्थिति हमसे भी बुरी है। लेकिन हम बेहद कड़े जैव सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं और अगले सप्ताह हमारा टीकाकरण भी होगा, इसलिए उम्मीद है कि सरकार हमें निजी विमान में स्वदेश लौटने की अनुमति देगी। ''

14 खिलाड़ी अभी भी खेल रहे हैं आईपीएल

बता दें कि लीग मैच 23 मई को समाप्त होंगे। इसके बाद 25 और 28 मई को दोनों क्वालीफायर जबकि 26 मैच को एलिमिनेटर खेला जाएगा। फाइनल 30 मई को होगा। ये सभी मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। आस्ट्रेलिया के 14 खिलाड़ी अब भी आईपीएल से जुड़े हैं। इनमें स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और पैट कमिन्स के अलावा दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच साइमन कैटिच भी शामिल हैं।

कोरोना की वजह से मुश्किल में राजस्थान रॉयल्स, दूसरी टीमों से लोन ले सकते हैं खिलाड़ी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स की टीम 14वें सीजन में मुश्किल में नजर आ रही है। टीम ने अब तक 5 मैच खेलने के बाद सिर्फ दो ही जीत मिली है। इस सीजन में टीम अपने स्टार खिलाड़ी की कमी झेल रही है। चोट, बायो-बबल थकान और कोविड-19 के तनाव के कारण चार विदेशी खिलाड़ियों के हटने से परेशानी का सामना कर रही है।

टूर्नामेंट की शुरुआत में ही राजस्थान की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा जब स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स चोट की वजह से बाहर हो गए। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी चोटिल होने के कारण आइपीएल से बाहर हैं जबकि लियाम लिविंगस्टोन घर लौट गए। सोमवार को खबर आई कि एंड्रयू टाई भी हट गए हैं। खिलाड़ियों के हटने के कारण राजस्थान सबसे बुरी तरह प्रभावित टीम बन गई है।

राजस्थान रॉयल्स ने आइपीएल के मौजूदा सत्र के लिए दूसरी टीमों से खिलाड़ियों को लोन पर लेने के लिए संपर्क किया है। टीम के एक सूत्र ने कहा, टीम खिलाड़ियों को लोन पर लेने की योजना बना रही है और इसके बारे में अन्य फ्रेंचाइजियों को लिखा है, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं हुआ है। आइपीएल का लोन समय (लोन विंडो) सोमवार को शुरू हुआ है और यह लीग मैचों के खत्म होने तक जारी रहेगा। आइपीएल नियमों के मुताबिक दो से कम मैच खेलने वाले खिलाड़ी को लोन पर दिया जा सकता है और वह अपने घरेलू फ्रेंचाइजी के खिलाफ नहीं खेल सकता है।

राजस्थान की टीम इस वक्त अंक तालिका में छठे नंबर पर है। टीम ने 5 मैच खेलने के बाद टीम के खाते में 3 हार और दो जीत है। पंजाब के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद दिल्ली को राजस्थान ने 3 विकेट से हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद पिछले मैच में टीम ने कोलकाता को ही हराया था।

ICC का बड़ा ऐलान, Commonwealth Games 2022 में इन 6 टीमों ने किया क्वालीफाई

नई दिल्ली। अगले साल इंग्लैंड में होने वाले कॉमन वेल्थ गेम्स में खेलने वाली क्रिकेट टीमों के नाम सामने आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोमवार को उन टीमों के नाम की घोषणा की जो 2022 में होने वाले इस गेम्स में जगह बनाने नें कामयाब रहे हैं। इस टूर्नामेंट में क्वालीफाई करने वाली टीमों के नाम की घोषणा करने वाली आइसीसी पहली संस्था है। अगले साल 28 जुलाई से आठ अगस्त के बीच इन खेलों का आयोजन इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में होने वाला है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कैरिबियन क्षेत्र टीम और और मेजबान इंग्लैंड ने इसमें क्वालीफाई किया है। आइसीसी और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने सोमवार को 2022 कॉमनवेल्थ में भाग लेने वाली महिला क्रिकेट टीम के नामों की घोषणा की। 22 साल के इतिहास में पहली बार महिला क्रिकेट टीमें इसमें भाग लेने जा रही है। साल 1998 में पुरुष टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में प्रतियोगिता हुई थी। क्वालुमपुर में हुए इस कॉमनवेल्थ गेम्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने बाजी मारी थी। अगले साल के इस प्रतियोगिता के लिए 5 टीमें होंगी जो मेजबान इंग्लैंड के साथ इसका हिस्सा बनेंगी। टी20 फॉर्मेट में होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम को शामिल किया गया है। 1 अप्रैल 2021 को आइसीसी द्वारा जारी महिला टी20 रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल करने वाली टीमों को ही क्वालीफिकेशन मिली है। जहां तक क्वालीफिकेशन प्रकिया की बता है तो इसमें खेलने वाली वेस्टइंडीज की टीम कौन सी होगी इसका फैसला इवेंट से तय होगा।

हॉकी पर भी कोरोना का साया

कैंप से पहले महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल सहित 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव; दो सपोर्टिंग स्टाफ भी संक्रमित

बैंगलुरू टोक्यो ओलिंपिक की तैयारी के लिए कैंप शुरु होने से पहले महिला हॉकी टीम को झटका लगा है। कप्तान रानी रामपाल सहित सात खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इसके अलावा दो सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्यों का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। महिला हॉकी टीम का कैंप 25 अप्रैल से शुरु होना था।

कैंप में शामिल सभी 25 खिलाड़ी 10 दिन के ब्रेक के बाद एक फिर से कैंप के लिए आए थे। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत सभी खिलाड़ी एक हफ्ते के क्वारैंटाइन में रहे। इस दौरान सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की कोरोना जांच की गई।

किसी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे

कप्तान रानी रामपाल के अलावा सविता पूनिया, शर्मिला देवी, रजनी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और सुशीला देवी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा वीडियो विशलेषक अमृतप्रकाश और वैज्ञानिक सलाहकार वेन लोम्बार्ड भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि किसी में भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (साई) के अधिकारियों के मुताबिक सभी साई की मेडिकल टीम की निगरानी में है।

अर्जेंटीना-जर्मनी के दौरे पर गई थी महिला टीम ओलिंपिक की तैयारी को ध्यान में रखते हुए महिला टीम ने जनवरी में अर्जेंटीना का दौरा किया था। वहां पर टीम ने अर्जेंटीना की जूनियर, बी टीम और सीनियर टीम के खिलाफ सात मैच खेले थे। अर्जेंटीना टीम की वर्ल्ड रैंकिंग दो है। भारतीय टीम ने तीन मैच ड्रॉ खेले, जबकि चार मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं फरवरी में जर्मनी के दुसेलदोर्फ गई थी। भारतीय टीम ने जर्मनी के साथ चार मैच खेले थे।

भारतीय महिला हॉकी ने तीसरी बार ओलिंपिक का टिकट हासिल किया है

भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरी बार ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। साल 1980 में पहली बार महिला टीम ने मॉस्को ओंलिपक में शिरकत की थी। इसके 36 साल बाद 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई की। हालांकि भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा था। वहीं तीसरी बार टोक्यो ओलिंपिक के लिए भारतीय महिला टीम क्वॉलिफाई की है और पहली बार लगातार दो ओलिंपिक में भाग लेगी।

राहत: एनडीटीएल पर लगे प्रतिबंध पर फैसले को तैयार वाडा, भारत सरकार ने दिए करोड़ो रुपये

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय की ओर से वाडा को डोपिंग के खिलाफ लड़ाई और शोध के नाम पर साढ़े सात करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि देने के बाद नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी (एनडीटीएल) पर लगे प्रतिबंध के हटने की उम्मीद जगी है। वाडा लैब पर लगे प्रतिबंध पर फैसला लेने को एनडीटीएल की ओर से किए गए सुधारों की वर्चुअली समीक्षा को तैयार हो गया है। वाडा अध्यक्ष विटोल्ड ब्लांका ने खेल मंत्रालय को यह जानकारी दी है। हालांकि वाडा अध्यक्ष ने यह नहीं बताया है कि यह ऑडिट कब होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वाडा का लैब एक्सपर्ट ग्रुप (एलईजी) जल्द समीक्षा करेगा। वाडा अध्यक्ष ने यह भी साफ किया है कि नए वाडा कोड के अनुसार लैब को स्वतंत्र रहना होगा। उन्होंने लैब के स्वतंत्र प्रभार के लिए एक जनवरी 2022 तक की मोहलत दी है।

समीक्षा को राजी

अध्यक्ष ने कहा है कि वाडा विज्ञान विभाग की ओर से एनडीटीएल को बताया गया है कि कुछ आपत्तियां पूरी तरह हल नहीं होने के बावजूद उनके विशेषज्ञ इस फैसले पर पहुचें हैं कि लैब का आने वाले दिनों में वर्चुअली ऑडिट किया जाना चाहिए। जिससे लैब से जुड़े सभी तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की समीक्षा कर एनडीटीएल के वाडा एक्रिडिटेशन (मान्यता) पर फैसला लिया जा सके। उन्हें उम्मीद है कि एनडीटीएल और उनका स्टाफ लैब की मान्यता बहाली के इस महत्वपूर्ण चरण को पास करने के लिए वाडा विशेषज्ञों से खुले तौर पर बातचीत को तैयार है।

सरकारी नियंत्रण से बाहर हो लैब

वाडा ने 20 अगस्त 2019 को एनडीटीएल को तकनीकी, प्रशासनिक खामियों के बाद प्रतिबंधित कर दिया था। तब से ओलंपिक की तैयारियों के बीच में भारतीय खिलाड़ियों की डोप टेस्टिंग विदेशी लैबों में हो रही है। सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि वाडा लैब पर लगे प्रतिबंध को हटा लेगी।

उनके हिसाब से वाडा की आपित्तयां दूर की जा चुकी हैं। वाडा अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि लैब का वाडा कोड 2021 के अनुसार स्वतंत्र रहना जरूरी है। लैब पर सरकारी नियंत्रण नहीं रह सकता है। ऐसे में एक जनवरी 2022 से लैब स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए। हालांकि मंत्रालय वाडा कोड आने के बाद लैब को आईसीएमआर के संरक्षण में देने का फैसला लिया था, लेकिन उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी।

पोर्शे ग्रां प्री: सबालेंका को फाइनल में हराकर एश्ले बार्टी बनीं चैंपियन

2019 के बाद क्ले कोर्ट पर पहला खिताब

नई दिल्ली। शीर्ष रैंकिंग की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने रविवार को जर्मनी के स्टुटगार्ट में खेले गए फाइनल में आर्यना सबालेंका को 3-6, 6-0, 6-3 से हराकर पोर्शे ग्रां प्री खिताब अपने नाम किया जो 2019 फ्रेंच ओपन के बाद क्ले कोर्ट पर उनका पहला खिताब है। सबालेंका पैर में पट्टी बांधकर खेल रही थी और उन्होंने तीसरे सेट से पहले मेडिकल टाइमआउट भी लिया। इस तरह बार्टी ने अपने करियर का 11वां खिताब अपनी झोली में डाला और उन्होंने लगातार तीसरी बार पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की है। बार्टी ने शनिवार को सेमीफाइनल में एलिना स्वितोलिना और क्वार्टरफाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को मात दी थी। अब बार्टी और जेनिफर ब्रैडी युगल फाइनल में डेसिरे क्रावजिक और बेथानी माटेक सैंड्स की जोड़ी से भिड़ेंगी।

कर हर मैदान फतह

जिस टीम को भेजने से डर रहे थे, उसने जीते चार पदक

नई दिल्ली। आखिर तीरंदाजों का जोखिम रंग लाया। अंतिम क्षणों में विश्व कप के लिए तीरंदाजी टीम रोकी जा रही थी, लेकिन दीपिका-अतानु समेत सभी ने एक स्वर में कहा कि वे हर हाल में यह विश्व कप खेलना चाहते हैं। तीरंदाजी संघ और साई को डर था कि टीम 24 घंटे से भी अधिक समय में तीन देश होकर ग्वाटेमाला जा रही है। उन्हें टीम के फंसने का डर था। बावजूद इसके तीरंदाजों ने जोखिम लिया।

दीपिका बोलीं जोखिम के अलावा नहीं था चारा: दीपिका ने ग्वाटेमाला से अमर उजाला से खुलासा किया यह सच्चाई है कि दौरा रद्द होने जा रहा था। वह और पूरी टीम जोखिम लेकर यहां आए। लेकिन यहां सुरक्षा के साथ अपना ध्यान रख रहे हैं। दीपिका कहती हैं कि जोखिम लेने के अलावा चारा नहीं था। यह सोचकर बैठा नहीं जा सकता है कि संक्रमण हो जाएगा तो क्या करेंगे। दरअसल तीरंदाजों ने डेढ़ साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला था। बमुश्किल यह विश्व कप खेलने को मिल रहा था। पहले वीजा में दिक्कत आई। कोशिशों के बाद

ग्वाटेमाला दूतावास को समझाया गया कि वीजा के लिए तीरंदाज दिल्ली नहीं लाए जा सकते। टिकट मिला तो तीन देशों से होकर जाना पड़ रहा था। जाने वाले दिन कंपाउंड कोच संक्रमित पाए गए। इस टीम को वहीं रोक दिया गया। एएआई महासचिव प्रमोद चंद्रूकर केमुताबिक टीम रवानगी से एक दिन पहले सभी रीकर्व तीरंदाजों ने जूम बैठक में साफ किया कि वे हर हाल में विश्व कप में जाएंगे।

गवर्नर्स कप: सेमीफाइनल में हारे अमित पंघाल, कांस्य पदक से ही करना पड़ा संतोष

नई दिल्ली। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके मुक्केबाज अमित पंघाल (52 किग्रा) को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चल रहे गवर्नर्स कप के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन और चिर प्रतिद्वंद्वी शेखोबिदीन जोइरोव से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित को उज्बेकिस्तान के गत ओलंपिक चैंपियन जोइरोव के हाथों 0-5 से शिकस्त मिली।

विश्व चैंपियनशिप 2019 के बाद जोइरोव के खिलाफ भारतीय मुक्केबाज की यह दूसरी हार है। अमित को विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जोइरोव ने हराया था। दोनों मुक्केबाज जुलाई-अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों का टिकट कटा चुके हैं। जोइरोव

को इस साल बुल्गारिया में स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारत के एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक कुमार ने हराया था।

आशीष कुमार (75 किग्रा) और सुमित सांगवान (81 किग्रा) के जल्द बाहर होने के बाद अमित ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया। ओलंपिक में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हरियाणा के अमित को टोक्यो खेलों में पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। 23 वर्षीय यह हरियाणवी मुक्केबाज पिछले तीन साल से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे।

निराश विलियमसन: सुपर ओवर में हार के बाद छलका दर्द, पुराने जख्म भी हुए ताजा

नई दिल्ली। विश्व कप हो या आईपीएल, केन विलियमसन सुपर ओवर में मिलने वाली हार से त्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल के मैच में विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में पराजय झेलनी पड़ी। मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा, 'मैं सुपर ओवर की हार से तंग आ चुका हूं।'उन्होंने कहा, 'पूरे मैच में जब भी सुपर ओवर होता है तो काफी सकारात्मक चीजें निकलती है। क्रिकेट वाकई अप्रत्याशित है, जिसमें मैच टाई हो जाते हैं लेकिन काफी रोमांचक था। मैच से ह्मारे लिए काफी कुछ सकारात्मक था। विश्व कप 2019 के फाइनल में भी इंग्लैंड ने सुपर ओवर में स्कोर बराबर रहने के बाद चौकों छक्कों की गिनती के आधार पर न्यूजीलैंड को हराया था। इस प्रारूप में काफी कम अंतर होता है। हमें खेल के बाकी पहलुओं में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यदि ऐसा कर सके तो नतीजे सकारात्मक रहेंगे।' यह इस सत्र का पहला सुपर ओवर मुकाबला था। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने सात रन बनाए। कप्तान डेविड वॉर्नर का शॉर्ट रन हैदराबाद को भारी पड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने दो रन लिए, लेकिन वह अपना पहला रन रन पूरा नहीं कर सके थे और दूसरे के लिए दौड़ पड़े थे। ऐसे में अंपायर ने इसे शॉर्ट रन करार दिया और टीम के खाते में एक ही रन जोड़ा।

कोलकाता ने पंजाब को 5 विकेट से हराया: केकेआर की लगातार 4 हार के बाद पहली जीत

जाब टीम को पिछले 6 मैच में 5वीं बार शिकस्त दी

चेन्नई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार 4 हार के बाद पहली जीत दर्ज कर ली। टीम ने आईपीएल 2021 सीजन के 21वें मैच में पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। 6 मैच में दूसरी जीत के साथ केकेआर टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई। मैच से पहले टीम सबसे आखिरी यानी 8वें नंबर पर थी। वहीं, पंजाब किंग्स के खिलाफ कोलकाता टीम की यह पिछले 6 मैच में 5वीं जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए। इसके जवाब में कोलकाता टीम ने 5 विकेट गंवाकर 16.4 ओवर में ही 126 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान ओएन मोर्गन ने 40 बॉल पर नाबाद 47 रन और राहुल त्रिपाठी ने 32 बॉल पर 41 रन की पारी खेली। पंजाब किंग्स के लिए मोइसेस हेनरिक्स, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और दीपक हुड्डा ने 1-1 विकेट लिया। कम स्कोर डिफेंड करते हुए भी पंजाब के दो बॉलर अर्शदीप और दीपक काफी महंगे साबित हुए। दोनों ने 10-10 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए।

मोर्गन और राहुल की पार्टनरशिप ने केकेआर को जिताया

124 रन के टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता टीम की शुरुआत

बेहद खराब रही। टीम ने 9 रन पर ही दोनों ओपनर गंवा दिए। पहले हेनरिक्स ने नीतीश राणा को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद शमी ने शुभमन गिल को शिकार बनाया। गिल ने 9 रन बनाए।

टीम 8 रन ही जोड़ सकी थी कि तीसरा झटका भी लग गया। अर्शदीप सिंह ने सुनील नरेन को जीरो पर आउट किया। रवि बिश्नोई ने उनका शानदार कैच लपका। यहां से कप्तान ओएन मोर्गन ने राहुल त्रिपाठी के साथ पारी को संभाला। दोनों ने टीम का स्कोर 43 बॉल पर ही 50 तक पहुंचा दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 48 बॉल पर 66 रन की पार्टनरशिप की। कोलकाता टीम को 83 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। दीपक हुड्डा ने राहुल को कैच आउट कराया। 98 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। आंद्रे रसेल 10 रन बनाकर रनआउट हुए। आखिर में मोर्गन ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 20 गेंद बाकी रहते ही टीम को जिताया। कार्तिक ने चौका लगाकर मैच खत्म किया।

क्रिस गेल खाता भी नहीं खोल सके

पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 34 बॉल पर सबसे ज्यादा 31 और क्रिस जॉर्डन ने 18 बॉल पर 30 रन बनाए। कप्तान लोकेश राहुल और निकोलस पूरन 19-19 रन ही बना सके। नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए क्रिस गेल खाता भी नहीं खोल सके। फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा ने सिर्फ 1 रन ही बनाया। वहीं, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट झटके। स्पिनर सुनील नरेन और फास्ट बॉलर पैट कमिंस ने 2-2 विकेट झटके।

लगातार अंतराल में विकेट गंवाते हुए छोटे स्कोर पर सिमटी पंजाब टीम

पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद सधी हुई रही। ओपनर लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल ने 5 ओवर में 29 रन जोड़ दिए थे।

पावरप्ले के आखिरी ओवर में टीम को पहला झटका लगा। कप्तान लोकेश राहुल 20 बॉल पर 19 रन बनाकर आउट हुए। पैट कमिंस ने विकेट लिया। अगले ही ओवर में 38 के स्कोर पर टीम का दूसरा विकेट गिरा। तेज गेंदबाज शिवम मावी ने क्रिस गेल को बिना खाता खोल पवेलियन भेजा। टीम 42 रन तक ही पहुंची थी कि प्रसिद्ध कृष्णा ने तीसरा झटका दिया। उन्होंने दीपक हुड्डा को 1 रन पर कैच आउट कराया।

शुरुआती 3 विकेट गंवाने के बाद पंजाब टीम ने 10वें ओवर में 50 रन पूरे किए। 60 के स्कोर पर टीम ने चौथा विकेट भी गंवा दिया।

सुनील नरेन ने ओपनर मयंक अग्रवाल को पवेलियन भेजा। बाउंड्री पर राहुल त्रिपाठी ने उनका शानदार कैच लपका।

79 रन पर पंजाब टीम के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पहले नरेन ने मोइसेस हेनरिक्स को पवेलियन भेजा।

फिर वरुण चक्रवर्ती ने निकोलस पूरन को शिकार बनाया। यहां से शाहरुख ने पारी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया।

18 ओवर में टीम का स्कोर 7 विकेट पर 98 रन था। इसके बाद क्रिस जॉर्डन ने बड़े शॉट खेलकर टीम का स्कोर 120 के पार पहुंचाया। जॉर्डन ने 19वें ओवर में एक छक्के के साथ 11 रन बनाए। आखिरी ओवर में उन्होंने 2 लंबे छक्के जड़े। इस ओवर में टीम ने 14 रन जुटाए।